



# रामलला का अभिषेक कर उतारेंगे महाआरती - सीएम योगी



रामनगरी अयोध्या में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतीक्षा की वर्षगांठ को लेकर अयोध्या सज-धज कर तैयार है। तीन दिवसीय प्रतीक्षा द्वादशी के उत्सव का उल्लास शनिवार से छलकने लगेगी सीएम योगी आदित्यनाथ उत्सव का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री कुछ देर में अयोध्या पहुंच जाएंगे। पांच घंटे अयोध्या में रहेंगे। वे रामलला का अभिषेक कर महाभारती उतारेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे अंगद टीला पर पहली बार श्रद्धालुओं व मेहमानों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने प्राण-प्रतीक्षा की प्रथम वर्षगांठ पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं रामलला की प्राण-प्रतीक्षा की प्रथम वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सदियों के त्याग, तपस्या और संघर्ष से बना यह मंदिर हमारी संस्कृति और अध्यात्म की महान धरोहर है। मुझे विश्वास है कि यह दिव्य-भव्य राम मंदिर विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में एक बड़ी प्रेरणा बनेगा। रामभक्ति में झूमे हैदराबाद से पहुंचे किन्नर श्रद्धार्थप्राण प्रतीक्षा

की वर्षगांठ पर हैदराबाद से किन्नर समाज के श्रद्धालु दर्शन को पहुंचे। इस मौके पर वह भक्ति भाव से झूमते नजर आए। रामलला के दरबार में श्रद्धालु नाचते गाते पहुंचे। वह श्रीराम की भक्ति में लीन दिखे। आराध्य के दर्शन को आतुर श्रद्धालु परिवार के साथ राम दरबार में पहुंचे।

बालक राम की छवि के रूप में पहुँचा बालक रामलला के प्रति प्रेम में विह्वल लोग आराध्य के दर्शन को पहुँच रहे हैं। इसी बीच एक बालक पहुँचा, जो बालक राम की छवि का रूप धारण किए था। देखने के लिए लोग जमा हो गए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर उत्सव का माहौल है। राम मंदिर को भव्य

रूप में सजाया गया है। देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु दर्शन को पहुंच रहे हैं।

प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर श्रद्धालुओं का तांता अयोध्या स्थित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन को पहुंच रहे हैं।

बालक राम के लिए दिल्ली में तैयार किए गए विशेष वस्त्र राम मंदिर में विराजमान बालकराम पीताम्बरी पहनकर दर्शन देंगे। रामलला की उत्सव मूर्ति व बालक राम के लिए दिल्ली में विशेष वस्त्र तैयार किए गए हैं। इन वस्त्रों की बुनाई व कढ़ाई सोने-चांदी के तार से की गई है। साथ ही जगह-जगह

चांदी की छाप भी बनाई गई है।  
कुछ देर में **CM योगी पहुंचेंगे**  
अयोध्या, रामलला की श्रीपेठक  
कर जतरेंगे महाआरती और  
जन्मभूमि पर भव्य मंदिर में रामलला  
के विराजमान होने के प्रथम  
वार्षिकोत्सव प्रतिष्ठा द्वादशी पर  
शनिवार से 13 जनवरी तक विशिष्ट  
कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।  
पहले दिन 11 जनवरी को रामलला  
का महाभिषेक, श्रृंगार, भोग और  
प्राकट्य आरती होगी। इसके बाद  
दोपहर 2:00 बजे से 5:00 बजे तक  
मुख्य समारोह आयोजित होगा।  
इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी  
अदित्यनाथ करेंगे। तीनों दिन अर्द्ध-  
टीला पर रामचरितमानस का पाठ,  
रामायण प्रवचन, श्रीराम जन्म कथा  
और सांस्कृतिक संध्या आयोजित की  
जाएगी। रामलला के दर्शनार्थियों के  
लिए महाप्रसादमा का वितरण भी  
किया जाएगा। इसी कड़ई में श्रीराम  
राग सेवा और बधाई गान के भी  
कार्यक्रम होंगे। प्राण प्रतिष्ठा की  
वर्षगांठ समारोह के मौके पर तीनों  
दिन रामलला के सभी आरती पास  
और विशिष्ट दर्शन पास निरस्त  
रहेंगे। आरती के समय भी श्रद्धालु  
दर्शन कर सकेंगे। ऐसे में दर्शन  
अवधि में करीब डेढ़ घंटे की वृद्धि  
हो जाएगी।

## मप्र एटीएस के इंस्पेक्टर सहित नौ पुलिसकर्मियों पर गुरुग्राम में हत्या का केस

साइबर ठगी के आरोपी की बालकनी से कूदने से हो गई थी मौत,  
एटीएस के इंसपेक्टर सहित नौ पुलिसकर्मी फंसे



थाना है। हिमांशु के परिवार ने एटीएस टीम पर टार्चर करने और बलाकनी से थक्का देकर नीचे के गिराकर हत्या करने का आरोप लगाया है। गुरग्राम पुलिस के अधिकारियों ने जांच के बाद हिमांशु को एटीएस टीम पर हत्या समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। सोहना पुलिस होटल के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच कर रही है, घटना के मूल कारणों की पता लगाया जा सके। इधर एमपी एटीएस का दावा है कि वह टेरेर फंडिंग की पुष्टा सूचना के बाद ही पूछाछ करने के लिए चारों युवकों को उठाया था। हिमांशु और उसका एक और दोस्त टेरेर फंडिंग के मुख्य सूत्रधार थे।

बारत नहीं होने से उलझी एम्पी  
एटीएस टीम पुलिस हिरासत में  
लेकर पूछताछ के दौरान संदिग्ध  
की मौत का यह पहला मौक़ा  
नहीं है। दूसरा राज्य होने और  
संदिग्धों से पूछताछ का कोई वारंट  
नहीं होने, स्थानीय पुलिस को  
अपने ऑपरेशन में शामिल नहीं  
करने के कारण एम्पी एटीएस को  
स्थानीय पुलिस हिमांशु की मौत के  
बाद सहयोग नहीं कर रही और  
हत्या जैसे संगीन अपराध में  
प्रकरण दर्ज किया है। अगर  
संदिग्धों से पूछताछ का कोई वारंट  
या पहले से कोई अपराध दर्ज होता  
तो एम्पी पुलिस बच सकती थी।  
पुलिस का दावा- हिमांशु टेरेर  
फंडिंग का मुख्य सूत्रधार, एम्पी  
मप्र पुलिस के आला अधिकाइयों  
ने दावा किया है कि एटीएस की  
टीम पुखा सूचना के बाद दबिश  
देने पहुँची थी। चार युवकों से  
पूछताछ कर रही थी। संदिग्धों के  
प्राप्त से एक दर्जन से अधिक  
लैपटॉप, टैबलेट, तीन दर्जन से  
अधिक मोबाइल फोन और करीब  
80 एटीएस कार्ड बरामद किए गए  
हैं। हिमांशु बिहार से पढ़ाई करने  
आएँ और पुलिस-सेना भर्ती की तैयारी  
करने दिल्ली आया था, लेकिन यहाँ  
वह पैसों की लालच में टेरेर फंडिंग  
में फँस गया। टेरेर फंडिंग का मुख्य  
सूत्रधार हिमांशु को ही बताया जा  
रहा है, जबकि उसके साथी भी  
इन्हें शामिल थे। हिमांशु की मौत  
के बाद बाकी को पुलिस ने छोड़  
दिया है, लेकिन अब मामले की  
जांच मध्यप्रदेश साइबर सेल और  
एटीएस दोनों एजेंसियाँ मिलकर  
कर रही हैं।

## सीएम डॉ. यादव बोले- पीएससी के तीन वर्ष के पद 2025 में भरे जाएंगे



भीपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को भीपाल में विभिन्न विभागों में चयनित शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें कहा कि राज्य के विभिन्न प्रशासनिक विभागों में चयनित अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न विभागों में चयनित अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न विभागों में चयनित अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है।

करें, जीवन में आगे बढ़ें, प्रदेश और समाज को आगे बढ़ाएं, इस उद्देश्य से राज्य सरकार सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए तत्पर है। युवाओं के जीवन में एक नया सूर्य उगे, वे अपने जीवन को आलौकिक करें, अपनी ऊर्जा का समाज हित में उपयोग करें, युवा दिवस के संदर्भ में युवाओं से यही अपील है।

प्रदेश में सभी भूमिजाँ तेज गति से  
 की जाएँगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि  
 युवा दिवस के अवसर पर प्रदेश की  
 लाडली बहनों को जनवरी माह की  
 अनुदान राशि का अंतरण कालापपीबल  
 जुला शाजापुर से किया जाएगा।  
 विवाओं को उन्नति और प्रगति के सभी  
 अवसर प्राप्त हों इस उद्देश्य से राज्य  
 सरकार बहुआयामी गतिविधियाँ  
 संचालित कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ.  
 यादव ने कहा कि हमने सरकार के  
 गठन के समय कहा था कि प्रदेश में  
 सभी भूमिजाँ त्वरित गति से की  
 जाएगी।

**पोर्न स्टार केस...सजा पाने वाले अमेरिकी इतिहास के पहले राष्ट्रपति बने ट्रंप**



भरना पड़ेगा। हालांकि वे एक अपराधी साबित हो चुके शख्स के तौर पर अमेरिकी

राष्ट्रपति की शपथ लेंगे जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचेगा। जस्टिस मर्चेन ने

कोर्ट को कहा कि इस देश के सर्वोच्च पद (राष्ट्रपति) की शक्तियों में दखलंदाजी किए बिना बगैर ट्रम्प को बिना शर्त छोड़ना ही सही सजा होगी। ट्रम्प ये सुनकर चुप रहे और उनकी स्क्रीन एकदम से बंद हो गई।

## शपथ ग्रहण से ठीक 10 दिन पहले सजा

ट्रम्प को उनके शपथ ग्रहण से ठीक 10 दिन पहले सजा सुनाई गई। उन्हें ये सजा पिछले साल जुलाई में ही सुनाई जानी थी, जिसका खामियाजा उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ा। इसके चलते वे बार-बार सजा को टलवाते रहे। ट्रम्प ने 6 नवंबर को हुए अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में जीती हासिल हुई थी और वे 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं। ट्रम्प ने सजा से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। हालांकि सुप्रीम ने गुरुवार को उनकी अपील खारिज कर दी थी।

करने की तैयारी कर रही है। वहीं आरोपी संजय कृषि का काम करता है।

मकान खाली कर कुछ सामान  
छोड़ दिया था बीएनपी थाना  
प्रभारी अमित सोलंकी ने बताया  
कि मकान मालिक भीरोद  
श्रीवास्तव ने जुलाई 2023 में यह  
मकान संजय पाटीदार को किराया  
पर दिया था। संजय ने जून 2024  
में मकान खाली कर दिया, लेकिन  
एक कमरे में अपना कुछ सामान  
छोड़ दिया था, जिसमें एक फ्रिज  
भी शामिल था। इसी फ्रिज में शव  
छिपा दिया था। उसने मकान  
मालिक से कहा था कि वो कमरा  
बाद में खाली कर देगा। मकान में  
रहने वाले दूसरे किराएदारों के  
मुताबिक संजय कभी कभी मकान  
पर आया करता था और अकेला  
ही आता था।

जब लाइट कट गई तो आने लगी दुर्गंध बताया जा रहा है कि रात के समय में जब लाइट कट गई तो कमरे से दुर्गंध आने लगी जिससे परेशान होकर उसी मकान में रहने वाले किराएदार बलवीर सिंह ने मकान मालिक के साथ ही

बैंक नोट प्रेस थाना पुलिस को फोन कर इसकी सूचना दी। मौके पर पुलिस ने महिला का शव बरामद किया था। आरोपी संजय पाटीदार उसी मकान में किराएदार था। जून माह में वह मकान खाली कर चुका है, लेकिन फ्रिज समेत कुछ सामान यहां दो कमरों में मौजूद था।

साड़ी और चूड़ी बेचती थीं। महिला पड़ोसियों का कहना है कि महिला इस मकान में रहकर साड़ी और चूड़ी बेचने का काम करती थी। वर्तमान में मकान में बलवीर सिंह अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। वे पिछले चार महीने से यहां किराए पर रह रहे हैं। मकान का किराया 7 हजार रुपए है। बलवीर सिंह ने बताया कि मकान में दो कमरे पहले के किराएदार ने खाली नहीं किए थे, जिनमें एक मास्टर बेडरूम और एक स्टडी रूम शामिल था। इन्हीं में से एक कमरे में फ्रिज रखा हुआ था। शुक्रवार को बलवीर सिंह ने बदवू के कारण उस कमरे का ताला तोड़ दिया और फ्रिज खोला, तब इस भयावह घटना का खुलासा हुआ।

आर्मी चीफ बोले- वेतन के लिए नहीं  
वतन के लिए फौज में आए...

ई दिल्ली। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि अगर मैं होता मैं नहीं होता तो या तो नेवी में सम्मरीनर होता या फिर एयरफोर्स में फाइटर पायलट होगा। एक कार्यक्रम में जनरल द्विवेदी ने बताया कि मौजूदा एयरफोर्स चीफ मेरे कोसमेंट है और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि अगली बार जब वैभारत निर्मित एलएसटी तेजस प्लाईअफ में भी उनके साथ उड़ान भरूंगा। जनरल द्विवेदी ने कहा कि हमारी थल-सीडीएस जनरल सिंघिन रावत कहां करुते थे- खामोशी से बनाओ एवधान अफी. हवाएं खुद ब खुद तुम्हारा तराना गाएंगी। मतलब हाई वर्क करो, लक्ष्य टय करो, लेकॉग में लिए भलाई का काम करो, टीम को साथ लेकर चलो। शोहरत या रिकॉगिजेशन आपको खुद आपको खुद मिलेगा। उन्होंने कहा कि मेरा सभी को एक ही मैसेज है कि आज जो भी जिन्दगी में करना चाहते हो उसके लिए आज से तैयारी शुरू करो और लग जाओ। अगर फौज में आना चाहते हो तो फौज एक अच्छा जरिया है जिसके जरिए आप अपनी उमंगों को, एडवेंचर को सब हासिल कर सकते हैं। लेकिन फौज में आना चाहते हैं तो वतन के लिए आप वतन के लिए नहीं। आमी चीफ ने कहा कि हमारे टीचर्स अपने परिवार से ज्यादा हमारा ख्याल रखते थे और हमेशा यही सम्झाते थे बेटा कितने भी बड़े बन जाओ हमेशा जमीन प रहें।

सीढ़ियां चढ़ने समय कक्षा तीन की छात्रा की कार्डियक अरेस्ट से मौत

अहमदाबाद / गुजरात में अहमदाबाद में कार्डियक अरेस्ट से तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली एक बच्ची की स्कूल में मौत हो गई। बच्ची अपने गैर और डिफिन बॉक्स को लेकर कॉरिडोर में मौजूद थी। तभी उसे स्कूल के कॉरिडोर को लेकर डिटक महसूस हुई। वह कॉरिडोर में पड़ी एक लंबी कुर्सी पर बैठ गई। कुछ ही सेकेंड बाद तीसरी कक्षा की छात्रा वहीं पर गिर पड़ी। सीप में मौजूद महिला स्टॉफ ने बच्ची को उठाया लेकिन उसे सीपीआर दिया गया। इसके बाद बच्ची की अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। डॉक्टरों ने बच्ची की मौत की जगह कार्डियक अरेस्ट बताई है। वह चौकाने वाली घटना अहमदाबाद के थलेन्ड इलाके में रिश्त जेवर स्कूल फॉर चिल्ड्रन में सामने आई। जानकारी के अनुसार तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा को सीने में दर्द की शिकायत हुई। इसके बाद उनकी मौत हो गई। छात्रा की पहचान गांभी रानपारा (करीब 9 साल) नाम की एक लड़की सुबह करीब 7.30 बजे ऑटो-रिक्शा से स्कूल पहुंची थी। स्कूल के कर्मचारियों ने बच्ची को सीपीआर दिया, लेकिन जब वह नहीं उठी, तो उसे पास के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी मौत कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई। स्कूल की प्रिंसिपल शर्मिष्ठा सिन्हा ने कहा कि लड़की के माता-पिता मुंबई में थे। उन्हें सूचित किया गया। भर्ती के समय हमने यह पुष्टि करने वाले दस्तावेज लिए थे कि बच्ची को कोई बीमारी नहीं थी।



## डकाच्या से लेकर पीथमपुर के बीच 77 किमी लंबे पूर्वी रिंगरोड पर खर्च होंगे चार हजार करोड़

**सिटी चीफ इंदौर।**  
इंदौर। डकाच्या से लेकर पीथमपुर के बीच बनने वाली पूर्वी रिंगरोड को लेकर रास्ता साफ हो गया है। सड़क को बनाने का काम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) को सौंप दिया है। 77 किमी लंबे इस मार्ग के निर्माण में चार हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।  
यह निर्णय गुरुवार को एयरपोर्ट लाउज में बैठक में रखी गई, जिसमें सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने सड़क बनाने के लिए जमीन से जुड़ी प्रक्रिया प्रदेश सरकार को पूरी करने पर जोर दिया। मौके पर मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव भी मौजूद थे, जिन्होंने भूमि अधिग्रहण जल्द शुरू करने पर सहमति दी। बैठक में एनएचएआइ के विभिन्न प्रोजेक्ट पर चर्चा की गई। सिंहस्थ के लिए उज्जैन



को जोड़ने वाली पश्चिमी-पूर्वी रिंगरोड बनाने को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। पश्चिमी रिंगरोड एनएचएआइ बना रहा है।  
परंतु अभी तक पूर्वी रिंगरोड को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई थी, क्योंकि सड़क बनाने को लेकर एजेंसी तय करना बाकी था। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) और एनएचएआइ पर प्रदेश सरकार मंथन करने में लगी थी।  
**38 गांव से निकलेगी सड़क**  
चार हजार करोड़ रुपये से बनने वाली पूर्वी रिंगरोड के अंतर्गत सड़क 38 गांव से गुजरेगी, जिसमें कपेल, खुडैल, तिल्लौर, बड़गोंदा, पीथमपुर सहित कई गांव शामिल हैं।  
सड़क को दो हिस्सों में बनाया जाएगा, जिसमें 38 और 39 किमी हिस्सा रखा गया

है। अधिकांश सरकारी जमीन से सड़क निकालेंगे। इसमें वनभूमि भी शामिल है।  
**जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अधूरी**  
पश्चिमी रिंगरोड को लेकर भी बैठक में बातचीत की गई। 64 किमी लम्बे रिंगरोड के लिए 638 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी तक खत्म नहीं हुई है।  
इंदौर और धार के 39 गांव आएंगे। 80 मीटर चौड़ी सड़क रहेगी।  
महू के पास एबी रोड से सांवेर होते हुए शिप्रा तक सड़क बनाए है, जिसमें बेटमा, हातोद, सांवेर, तराना होते हुए क्षिप्रा से सड़क निकाली जाएगी।  
सड़क को लेकर 48 हेक्टेयर वनभूमि की जरूरत है, जिसमें 40 हेक्टेयर इंदौर वनमंडल और 8 हेक्टेयर धार वनमंडल का वनक्षेत्र है।

## जीएसटी पोर्टल ठप, रिटर्न भरने की तारीख दो दिन बढ़ी

**सिटी चीफ इंदौर।**  
जीएसटी के मासिक और त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि दो दिन बढ़ा दी गई है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) ने शुक्रवार शाम इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी। जीएसटी पोर्टल के ठप होने के चलते यह निर्णय लिया गया। दो दिनों से जीएसटी पोर्टल पर रिटर्न ही दाखिल नहीं हो रहे थे। गुरुवार शाम तक पोर्टल बंद रहा। शुक्रवार को फिर सुबह से पोर्टल पर मेंटनेंस का संदेश आया और शाम 6 बजे बाद तक बंद रहा।  
इस बीच मप्र टैक्स ला बार एसोसिएशन, कमर्शियल टैक्स प्रेक्टिशनर्स एसोसिएशन ने ज्ञापन सौंपे। अलग-अलग राज्यों के कर पेशवरों ने भी ई-मेल और एक्स पर पोस्ट कर शिकायत की।  
जीएसटी के मासिक रिटर्न फार्म जीएसटीआर-1 को दाखिल करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी और त्रैमासिक पद्धति वालों के लिए इसकी पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि 13 जनवरी थी।  
तारीख बढ़ने से अब ये रिटर्न क्रमशः 13 जनवरी और 15 जनवरी तक भरे जा सकेंगे।  
हमेशा पैसों का निवेश करते चलें मेरा मानना है कि निवेश करते रहना चाहिए। समय-समय पर पैसों की बचत करते चलें और निवेश भी करते चलें। अक्सर होता यह है कि हम लोग अधिकतर समय सोचने में निकाल देते हैं।



समय निकलता चला जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। पता चलता है कि बुढ़ापा आ जाता है और हमारे पास एक रुपये तक बचत का नहीं रहता है।  
यदि भविष्य में आर्थिक रूप से समृद्ध बनना है तो निवेश करना शुरू करना ही पड़ेगा। इससे पहले पैसों की बचत करनी होगी।  
हर महीने पैसे बचाएं और एक से दो वर्ष में पैसे एकत्रित होने पेंशन प्लान में निवेश करें। साथ ही अलग-अलग कंपनियों की पालिसी लें।  
संभव हो जब हमारे दिन अच्छे चल रहे होते हैं, यानि हम खूब पैसे कमाते हैं, उस समय पैसे

जोड़कर निवेश जरूर कर लें।  
एक, दो, तीन, चार से पांच रुपये होने पर सोने-चांदी में निवेश कर दें। यह निवेश का सबसे अच्छा सेक्टर होता है। इसमें लाभ की अधिक संभावना होती हैं।  
सोने-चांदी के अलावा निवेश के अलग-अलग सेक्टर होते हैं। जैसे शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड आदि। इन सभी में भी थोड़ा-थोड़ा निवेश करते चलें। जब तक आप हर सेक्टर में थोड़ा-थोड़ा निवेश नहीं करेंगे, तब तक आपको लाभ नहीं होगा। निवेश का सबसे अच्छा लाभ लेना है तो समय पर सोच समझकर निवेश करें।



**सिटी चीफ इंदौर।**  
ऑनलाइन ट्रेडिंग और निवेश की राशि चारगुना करने लालच में डॉक्टर ने 3 करोड़ 4 लाख रुपये गवां दिए। साइबर अपराधियों ने डॉक्टर को विदेशी नंबरों से संचालित एक वाट्सएप ग्रुप से जोड़ा और उनके नाम से फर्जी पोर्टफोलियो भी बना लिया। अपराध शाखा मामले की जांच में जुटी है।  
कई बैंक खातों और मोबाइल नंबरों की जांच चल रही है। एडिशनल डीसीपी (अपराध) राजेश दंडोटिया के मुताबिक धोखाधड़ी एलआइजी कॉलोनी निवासी 53 वर्षीय डॉक्टर मोहन सोनी के साथ हुई है।  
**फेक ट्रेडिंग कंपनी**  
इसकी शुरुआत पिछले वर्ष 9 अगस्त को फेसबुक के माध्यम से हुई थी। इसके बाद आरती उर्फ आरु भट्ट ने कॉल लगाए और एक लिंक भेज कर डॉक्टर का वेबुल ट्रेडिंग कंपनी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दिया। डॉक्टर ने ऑनलाइन निवेश शुरू किया और उनके नाम से बने वॉलेट में चारगुना राशि नजर आने लगी।  
**विश्वास में आकर किए करोड़ों निवेश**  
डॉक्टर ने दो बार रुपये निकाले तो आसानी से खाते में बैलेंस आ गया। इससे कंपनी पर विश्वास कर आरु के कहे अनुसार एक करोड़ रुपये से ज्यादा निवेश कर दिए। पिछले साल दीपावली पर डॉक्टर ने रुपये निकालने का प्रयास किया मगर ग्राहक सेवा

केंद्र द्वारा बताया कि मुनाफा का 30 प्रतिशत आयकर टैक्स देना पड़ेगा। कंपनी इसकी रसीद देगी जो भारत में भी मान्य होगी।  
**आरबीआई द्वारा फ्रीज कराने की बात**  
डॉक्टर ने आरोपितों की बातों में आकर 55 लाख रुपये जमा करवा दिए। इस बार आरु ने डॉक्टर से कहा कि वेबुल कंपनी द्वारा तो रुपये ट्रांसफर कर दिए मगर भारतीय रिजर्व बैंक ने रोक लगा दी। रुपयों के लिए 30 लाख रुपये जमा कर ग्रीन चैनल ओपन करना होगा।  
**घबराहट में 30 लाख रुपये भी जमा करवाए**  
ऐसा न करने पर खाते में जमा रुपये डूब जाएंगे। डॉक्टर ने घबराहट में 30 लाख रुपये भी जमा करवा दिए। आरोपितों ने तीसरी बार डिजिटल करंसी एंड फंड एग्रीमेंट, डिजिटल करंसी एंड फंड सिक्युरिटी के नाम से 17 लाख 816 रुपये जमा करवाए।  
**खाते में जमा रुपयों का बीमा का झांसा देकर 25 लाख एंटे**  
आरोपितों ने कहा कि खाते में जमा रुपयों का इंटरनेशनल ब्लाक चेन सर्वर सिक्क्युरिटी बीमा करवाना पड़ेगा। वरना खाता और रुपये समाप्त कर देंगे। डॉक्टर 9 अगस्त से 29 नवंबर तक कुल 3 करोड़ 4 लाख रुपये आरोपितों द्वारा बताए खातों में जमा करवाते गए।  
डॉक्टर ने इंडसैंड, यस बैंक और एसबीआई से 64 बार ट्रांजेक्शन किया। रुपये जमा करवाने के बाद बेटे सोमित्र को घटना बताई

और नेशनल साइबर हेल्प लाइन नंबर 1930 पर शिकायत की। नोडल एजेंसी क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को मामले में केस दर्ज कर लिया।  
**स्फूफ कॉलिंग से कारोबारी को 70 लाख रुपये चपत**  
साइबर अपराध की चौकाने वाली घटना सामने आई है। अपराधियों ने स्फूफ कॉलिंग के माध्यम से एक कारोबारी के 70 लाख रुपये निकाल लिए। आरोपितों ने अकाउंटेंट का हूबहू आवाज में कॉल लगाया था। हालांकि तुरंत एक्शन में आई क्राइम ब्रांच ने आरोपितों का खाता फ्रीज कर रुपये बचा लिए।  
ए फि ड श 1 न ल डीसीपी (अपराध) राजेश दंडोटिया के मुताबिक फरियादी शेयर ब्रोकिंग फर्म का संचालक है। उसने पुलिस को बताया कि आरोपितों ने अकाउंटेंट को वाट्सएप कॉल लगाया था। डिस्ले पर फोटो और नंबर भी फर्म संचालक के नंबर थे और नाम भी सही था। उसने इमरजेंसी बता कर 70 लाख रुपये ट्रांसफर करने के निर्देश दिए।  
अकाउंटेंट धोखे में आ गया और आरोपितों द्वारा बताए खाते में रुपये ट्रांसफर कर दिए। कुछ देर बाद उसने रिटर्न कॉल लगाया तो संचालक ने बताया उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। उसने रुपये ट्रांसफर करने के लिए कॉल नहीं लगाया। मामले की साइबर हेल्प लाइन नंबर 1930 पर शिकायत की गई। पुलिस ने तत्काल खाते फ्रीज कर रुपये बचा लिए।

## सोनू बनकर लड़कियों को जाल में फंसाता था सोहेल

100 से अधिक युवतियों के साथ मिली Chat

**सिटी चीफ इंदौर।**  
इंदौर। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार दोपहर सोहेल खान नामक युवक को पकड़ा। मूलतः मनावर निवासी सोहेल पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। सोहेल के फोन में हिंदू युवतियों से चैटिंग मिली है। आरोपित सस्ते दामों पर मोबाइल और एसेसरीज देने का प्रलोभन देता था।  
**असली नाम जान चौंक गई लड़की**  
पदाधिकारियों के मुताबिक सोहेल मारवाड़ी को खंडवा रोड़ स्थित एक कैफे से पकड़ा गया है। वह कॉलेज छात्रा के साथ आया था। युवती से पूछने पर कहा सोहेल ने उसे सोनू मारवाड़ी नाम बताया था। वास्तविकता बताते पर युवती भी



चौंक गई। मौके पर समाजजन को बुलाया और युवती को समझाइस दी।  
**फोन में 100 लड़कियों के नंबर, देता था झांसा**  
सोहेल का फोन चेक करने पर करीब 100 युवतियों के नंबर

मिलें, जिसमें ज्यादातर कॉलेज छात्राएं थी। आरोपित उनसे हमला कर दिया। दूसरी तरफ से पिंकी यादव ने रवि मिठौरा, रौनक मिठौरा और ऋतु के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है।

मना कर दिया। पुलिस सोहेल के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर रही है।  
**युवती से बात करने पर विवाद, छह पर FIR**  
एरोड्रम थाना अंतर्गत धर्मराज कालोनी में बुधवार को दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। फरियादी ऋतु मिठौरा के मुताबिक आरोपित एकलव्य यादव बेटा से बात करता है।  
बेटा रौनक समझाने गया तो घनश्याम, अभिषेक आदी ने हमला कर दिया। दूसरी तरफ से पिंकी यादव ने रवि मिठौरा, रौनक मिठौरा और ऋतु के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है।

## महाकुंभ के लिए इंदौर से हर शनिवार फ्लाइट

4.5 हजार की टिकट के दाम हुए 20 हजार

**सिटी चीफ इंदौर।**  
इंदौर। प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और आरामदायक सफर के लिए इंदौर से अलायंस एयर ने सीधी विमान सेवा की घोषणा करते हुए एक सप्ताह पहले बुकिंग शुरू की गई थी। पहली उड़ान शनिवार रात्रि में रवाना होगी और इसकी सभी सीटें एक दिन पहले ही बुक हो गईं।  
**4.5 हजार का टिकट 20 हजार तक पहुंचा**  
दो घंटे में महाकुंभ में पहुंचने के लिए लोगों ने 15 से 20 हजार रुपये तक खर्च किए हैं। 3 जनवरी को टिकट साढ़े चार हजार का था, जो शुक्रवार को 20 हजार तक



पहुंच गया। आयोजित हो रहे महाकुंभ में उत्तरप्रदेश के प्रयागराज में देशभर के साथ ही इंदौर से बड़ी

संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए ट्रेन के साथ हवाई सफर की सुविधा भी उपलब्ध हो रही है।  
**शनिवार को इंदौर से उड़ान, सोमवार को प्रयागराज से**  
अलायंस एयर ने एक सप्ताह पहले प्रयागराज उड़ान की घोषणा करते हुए बुकिंग शुरू की थी। यह उड़ान जनवरी में सप्ताह में एक दिन शनिवार रात्रि में इंदौर से रवाना होगी और सोमवार को प्रयागराज से इंदौर आएगी।  
**सभी सीटें हुईं फुल**  
11 जनवरी को जाने वाले छोटे विमान की सभी 70 सीटें बुक हो

चुकी हैं। रविवार से ही फ्लाइट का टिकट जाने में 15 हजार पार पहुंच गया था। आने में भी टिकट के दाम इसके आसपास पहुंच गए हैं। ट्रेलव एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हेमेश सिंह जादोन का कहना है कि कुम्भ पहुंचने के लिए एक ही सीधी उड़ान होने से लोग अधिक बुकिंग करवा रहे हैं, इसलिए इसके फेयर बढ़े हुए हैं। उड़ान के कारण लोगों का जाने और आने का समय भी बच रहा है।  
**तीन दिन ही मिलेगी सुविधा**  
इंदौर-प्रयागराज उड़ान शनिवार को दिल्ली से इंदौर आकर प्रयागराज जाएगी और सोमवार

को प्रयागराज से इंदौर आकर दिल्ली जाएगी। इंदौर से प्रयागराज के लिए 11, 18 और 25 जनवरी को उड़ान संचालित होगी और प्रयागराज से इंदौर के लिए 13, 20 और 27 जनवरी को उड़ान संचालित होगी।  
**यह होगा इंदौर-प्रयागराज उड़ान का शेड्यूल**  
इंदौर-प्रयागराज – उड़ान संख्या 9आई 342 इंदौर से रात्रि 8.05 बजे रवाना होकर रात्रि 10.05 बजे प्रयागराज पहुंचेगी।  
प्रयागराज-इंदौर – उड़ान संख्या 9आई 340 प्रयागराज से रात्रि 7.40 बजे रवाना होकर रात्रि 9.40 बजे इंदौर पहुंचेगी।



# मप्र कांग्रेस ने खड़ी की बड़ी टीम, कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ साइडलाइन

**सिटी चीफ भोपाल ।** भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस के संगठन में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अलग-अलग विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी है। कांग्रेस कमेटी के अलग-अलग विभागों का इंचार्ज बनाया गया है। इस बदलाव में उन नेताओं को भी खुश करने की कोशिश की गई है जो कि जीतू पटवारी से नाराज नजर आ रहे थे। राजीव सिंह को पटवारी ने अपना राजनीतिक सलाहकार नियुक्त किया है। राजीव सिंह वहीं नेता हैं जिन्होंने संगठन प्रभारी पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी थी। प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव प्रबंधन को लेकर राजनीतिक सलाहकार, प्रशिक्षण विभाग, यूथ कांग्रेस मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, महिला कांग्रेस और एनएसयूआई जैसे 35 विभागों के



प्रभारी नियुक्त किए हैं। **दिग्गी राजा के बेटे को बड़ी जिम्मेदारी** पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे और राघोगढ़ से विधायक विभाग, यूथ कांग्रेस मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, महिला कांग्रेस और एनएसयूआई जैसे 35 विभागों के

की जोड़ी भी चर्चाओं में है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में छिंदवाड़ा से विधायक कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुल नाथ का नाम इस सूची में नहीं है। कयास हैं कि नाथ परिवार को लगातार कांग्रेस पार्टी में साइडलाइन का सामना करना

पड़ रहा है। जिसके कारण सियासी गलियारों में भी हलचल तेज हो गई हैं। **इनको भी मिली बड़ी जिम्मेदारी** पूर्व विधायक हिना कमेरे को महिला कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंप गई है। वहीं प्रियव्रत सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ ही चुनाव प्रबंधन का प्रभारी बनाया गया है। पूर्व मंत्री पीपी शर्मा सरकारी कर्मचारी संगठनों से समन्वय का काम देखेंगे। केके मिश्रा को प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का मीडिया सलाहकार बनाया गया है। जेपी धनोपिया चुनाव आयोग और कानूनी कार्य जबकि डॉक्टर आनंद राय को सिविल सोसाइटी संबंधी मामले का प्रभारी बनाया गया है। **इन नेताओं को भी मिले मौके** इसके अलावा ट्रेनिंग विभाग का प्रभारी महेंद्र जोशी, सह प्रभारी विभाग बिंदु डागोर को मिला है।

जीतू पटवारी के राजनीतिक सलाहकार राजीव सिंह को बनाया गया है। आतिफ अकील सह प्रभारी प्रशासकीय सम्मान, प्रशासन समन्वय प्रभारी आरिफ मसूद को बनाया गया है। संगठन उपाध्यक्ष प्रियव्रत सिंह, सह प्रभारी व जिला प्रभारी के समन्वय और मॉनिटरिंग प्रभारी चौधरी राकेश सिंह को बनाया गया है। सेल एवं डिपार्टमेंट के प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान, युवा कांग्रेस एंपावरमेंट प्रोग्राम प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन के प्रभारी जयवर्धन सिंह और सह प्रभारी पंकज उपाध्याय को बनाया गया है। इसके अलावा कई अन्य नेताओं को भी विभिन्न विभागों में मौका दिया गया है। **पीसीसी में पहली बार संगठन में दो प्रभारी बनाए** इससे पहले गुक्वार को ही प्रदेश कांग्रेस के संगठन प्रभारी राजीव

सिंह ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को पत्र लिखकर पद छोड़ने की पेशकश की। राजीव सिंह का इस्तीफा सामने आने के घंटे भर बाद ही पीसीसी में कार्य विभाजन हो गया। इस कार्य विभाजन में पटवारी ने पूर्व विधायक प्रियव्रत सिंह को उपाध्यक्ष संगठन और पीसीसी के प्रशासन प्रभारी संजय कामले को संगठन का प्रभारी नियुक्त कर दिया। कांग्रेस के प्रशासन की जिम्मेदारी कामले को जगह गौरव रघुवंशी को दी है। पीसीसी में पहली बार ऐसा हुआ है कि संगठन में दो प्रभारी बनाए गए हैं। राजीव सिंह ने गुक्वार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नाम पर पत्र में लिखा- हजोतू पटवारी जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर आपकी नियुक्ति को एक साल से अधिक समय हो गया है।

आपकी नियुक्ति के तुरंत बाद मैंने स्वयं ही आग्रह किया था कि मैं कई सालों से प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रभारी संगठन एवं प्रभारी प्रशासन के पद पर काम कर रहा हूं। नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए यह मेरी मान्यता है। क्योंकि, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हो गया है। कई लोगों को विभिन्न दायित्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा दिया गया है। राजीव सिंह ने आगे लिखा- मेरा पुनः आग्रह है कि प्रदेश कांग्रेस संगठन प्रभारी के पद पर आप किसी योग्य साथी को अवसर देने की कृपा करें। मैं प्रदेश कांग्रेस का पदाधिकारी होने के नाते राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व द्वारा संगठन के संबंध में जो भी काम और दायित्व मुझे दिए जाएंगे। मैं उनका निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ करता रहूंगा।

## भोपाल की सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा

# मंत्री सारंग ने खुद सामने खड़े होकर अवैध कब्जों पर चलवाई जेसीबी

**सिटी चीफ भोपाल ।** भोपाल। राजधानी भोपाल में के सरकारी जमीनों पर लगातार अवैध कब्जा बढ़ता जा रहा है नगर निगम भूमिया पर कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रहा है अब मंत्री विश्वास सारंग ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा हटाने की मुहिम छेड़ दी है। मंत्री सारंग लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की गई। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने खुद सामने खड़े होकर कार्रवाई करवाई। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री सारंग के निर्देश पर एसडीएम रवीश कुमार श्रीवास्तव ने करोंद इलाके में कार्रवाई की। यहां पर सरकारी जमीन पर प्लांटिंग की जा रही थी। यह देख मंत्री सारंग नाराज हो गए और उन्होंने तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मंत्री के निर्देश मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और निगम अमला हरकत में आ गया। कुछ ही देर में जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण भी हटा दिया गया। **भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई** मंत्री सारंग खुद नगर निगम अमले के साथ मौके पर पहुंचे और अवैध निर्माण को तत्काल तोड़ने के निर्देश दिए। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। ताकि, हंगामा होने पर सख्ती से निपटा जा सके। निरीक्षण के दौरान यह पाया कि सरकारी भूमि पर बिना अनुमति के निर्माण कार्य किया जा रहा था। मंत्री सारंग ने इसे गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए कि शासकीय भूमि पर हो रहे सभी अवैध निर्माण तुरंत प्रभाव से हटाए जाएं और भविष्य में इस तरह के मामलों को रोकने के लिए प्रभावी कदम



उठाए जाएं। **सरकारी जमीन पर कब्जा कर गरीबों को कर रहे गुमराह** मंत्री सारंग ने शासकीय भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फेंसिंग लगाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि भू-माफिया शासकीय जमीनों पर कब्जा कर गरीब जनता को गुमराह कर भूमि का विक्रय करते हैं। जिससे जनता और शासन दोनों का नुकसान होता है। शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री सारंग ने बताया, इस अभियान को और अधिक सख्ती से चलाया जाएगा। उन्होंने नगर निगम और प्रशासनिक

अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र में सर्वे के जरिए अवैध कब्जों की पहचान कर समय रहते उचित कार्रवाई करें। **एक दिन पहले भी हुई थी कार्रवाई** भोपाल के करोंद इलाके में सरकारी जमीन पर अवैध प्लांटिंग को शिकायत पर गुरुवार को भी मंत्री विश्वास सारंग औचक निरीक्षण करने निकले थे। जैसे ही मंत्री एक जगह पर पहुंचे, उन्हें देख अवैध प्लांटिंग कर रहे लोग गाड़ी छोड़कर भाग निकले थे। इस गाड़ी को पुलिस ने छेड़कर मजदूरों में ले लिया था। मंत्री ने करोंद, पलासी, बड़वाई और रसुल्ली क्षेत्र का निरीक्षण किया था।

# सीसीटीवी में जलती चिता के पास दिखा तांत्रिक, पुलिस के हवाले किया

**सिटी चीफ भोपाल ।** भोपाल- भोपाल के पास खजूरीकलां गांव के श्मशान में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। जिससे गांव के लोगों में दहशत का माहौल था। डर के मारे वहां जाने से भी लोग कतराने लगे थे। श्मशान घाट पर कभी काले पुतले तो कभी नींबू और सिंदूर मिल रहा था। इन घटनाओं ने ग्रामीणों की चिंता को भी बढ़ा दिया था। पर टेक का इस्तेमाल करके उन्होंने इस समस्या का समाधान कर लिया है। पर इसके पीछे जो खुलासा हुए देखकर सभी हैरान हैं। दरअसल, भोपाल से सटे खजूरीकलां गांव में श्मशान घाट पर लंबे से रहस्यमयी घटनाएं हो रही थी। लोगों का कहना था कि इस कारण वहां से तंत्र-मंत्र की चीजे मिलना शुरू हो गया था। जिससे गांववाले



दहशत में थे। इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगवाए।खजूरीकलां के श्मशान घाट का रखरखाव एक समिति करती है। यहां हर हफ्ते औसतन तीन लोगों का अंतिम संस्कार होता है। लेकिन पिछले डेढ़ साल से यहां

तांत्रिकों का आना-जाना बढ़ गया है। अंतिम संस्कार के बाद जब परिजन अस्थियां लेने आते हैं, तो उन्हें वहां तंत्र-मंत्र के सामान मिलते हैं। जैसे काले कपड़े के छोटे-छोटे पुतले, नींबू और सिंदूर जैसी चीजें। गांववालों ने इस पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने रात में श्मशान घाट पर सीसीटीवी की मदद से नजर रखनी शुरू कर दी। एक अमावस्या की रात, उन्हें कामयाबी मिली। उन्होंने एक जलती चिता के पास एक तांत्रिक को पकड़ लिया। वह श्मशान में तंत्र-मंत्र के मकसद से आया था। ग्रामीणों द्वारा उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। इससे उनका डर अब कुछ हद तक खत्म हो गया है। सीसीटीवी की मदद से अब वे घर बैठे भी श्मशान घाट में हो रही हलचल पर नजर रख सकते हैं।

# बिजली उपभोक्ताओं को डिजि लॉकर के माध्यम से मिलेगा बिजली बिल

**सिटी चीफ भोपाल ।** भोपाल। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए एक नई पहल की है। अब भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम और चंबल संभाग के 16 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को उनका बिजली बिल डिजिटल लॉकर के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जाएगा। यह कदम ह्यूडिजिटल इंडियाहू के तहत भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के रूप में लिया गया है, जो उपभोक्ताओं को डिजि प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुरक्षित और पेपरलेस दस्तावेज प्रदान करता है। डिजि लॉकर एक सार्वजनिक क्लाउड पर आधारित सुरक्षित दस्तावेज एक्सेस प्लेटफॉर्म है, जिसे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा, सूचना



प्रौद्योगिकी नियम 2016 के तहत, डिजि लॉकर के माध्यम से जारी किए गए दस्तावेजों

को मूल फिजिकल दस्तावेजों के बराबर माना जाता है।

**डिजि लॉकर से बिजली बिल तक पहुंचने के फायदे** इस नई सुविधा से उपभोक्ताओं को कई फायदे मिलेंगे। अब वे डिजि लॉकर के माध्यम से अपने बिजली बिलों तक आसानी से पहुंच सकते हैं और इन्हें सुरक्षित तरीके से संग्रहित भी कर सकते हैं। डिजि लॉकर से बिजली बिल के खोने, चोरी होने या नुकसान होने का खतरा नहीं रहेगा। इसके अलावा, यदि उपभोक्ता को पिछले बिल या डुप्लिकेट बिल की आवश्यकता हो, तो वह इसे डिजि लॉकर से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। आसान होगा बिलों को शेयर करना कंपनी ने बताया कि डिजि लॉकर के माध्यम से बिलों को शेयर करना भी आसान होगा। उपभोक्ता अपने बिलों को अन्य संस्थाओं जैसे बैंक, वित्तीय संस्थान या सरकारी

एजेंसियों के साथ भी आसानी से साझा कर सकते हैं। इस कदम से न केवल कागजी बिलों की आवश्यकता खत्म होगी, बल्कि यह एक सुरक्षित और सुविधाजनक तरीका होगा, जो उपभोक्ताओं को पेपरलेस भुगतान प्रक्रिया को अपनाने में मदद करेगा। **कैसे डाउनलोड करें बिजली बिल?** बिजली उपभोक्ता डिजि लॉकर एप को एंड्रॉयड या आईफोन पर डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आसानी से अपने बिजली बिल का डिजिटल संस्करण प्राप्त कर सकते हैं। यह पहल मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक आधुनिक और सुरक्षित तरीका प्रदान करती है, जिससे वे अपने बिजली बिलों को आसानी से, सुरक्षित रूप से और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से प्रबंधित कर सकेंगे।



जाएगा। जेल परिसर में ड्रोन मिलने का समाचार प्रकाशित होने के बाद डॉक्टर स्क्विन जैन जेल पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि वह महावीर मेडिकल कालेज में प्रोफेसर हैं और द्वारिका धाम में रहते हैं। उन्होंने अपने बेटे के लिए दिल्ली से यह ड्रोन खरीदा था। बीती 31 दिसंबर को आईटी पार्क से यह ड्रोन उड़ाया जा रहा था, लेकिन ऊंचाई ज्यादा होने के कारण संपर्क टूट गया और ड्रोन गायब हो गया था। उन्होंने ड्रोन का रिमोट भी अधिकारियों को दिया। अधिकारियों ने जब चेक किया तो वह रिमोट उसी ड्रोन का निकला। डॉक्टर ने ड्रोन खरीदने के कागजात भी प्रस्तुत किए हैं,

लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ड्रोन की फोरेंसिक जांच कराई जाएगी। इधर गुरुवार को गांधी नगर पुलिस जेल में मिले ड्रोन की जांच पड़ताल कर रही थी। टीम जब आरजीपीवी कैंपस पहुंची तो वहां भी एक पेड़ पर ड्रोन अटका हुआ मिला। यह ड्रोन जेल में मिले ड्रोन से बिल्कुल अलग है। हालांकि उसके अंदर कोई मेमोरी कार्ड अथवा संदिग्ध रिकार्डिंग नहीं मिली है। यह ड्रोन किसका है, इसको लेकर इलाके में एनाउंसमेंट करवाया गया है। प्रारंभिक पड़ताल में यह ड्रोन भी खिलौना जैसा लग रहा है, लेकिन इसकी भी तकनीकी और फोरेंसिक जांच करवाई जा रही है।



## राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह केवल रस्म बनकर न रह जाए

हमारे देश में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2015 से मनाया जा रहा है। यह हर साल 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन को यातायात नियमों की आधारभूत जानकारी मिलती है। लेकिन जरूरत यह है कि ये आयोजन केवल रस्म बनकर न रह जाएं। इन कार्यक्रमों से मिली जानकारी को लोग वाहन चलाते समय आदत में लेकर आए तो ज्यादा बेहतर होगा। आकस्मिक कारक के रूप में सड़क दुर्घटनाओं के विश्लेषण से पता चलता है कि कुल सड़क दुर्घटनाओं में 78.7 प्रतिशत दुर्घटनाएं चालकों की गलती से होती हैं।

हमारे देश में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2015 से मनाया जा रहा है। यह हर साल 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन को यातायात नियमों की आधारभूत जानकारी मिलती है। लेकिन जरूरत यह है कि ये आयोजन केवल रस्म बनकर न रह जाएं। इन कार्यक्रमों से मिली जानकारी को लोग वाहन चलाते समय आदत में लेकर आए तो ज्यादा बेहतर होगा। आकस्मिक कारक के रूप में सड़क दुर्घटनाओं के विश्लेषण से पता चलता है कि कुल सड़क दुर्घटनाओं में 78.7 प्रतिशत दुर्घटनाएं चालकों की गलती से होती हैं। इस गलती के पीछे शराब/मादक पदार्थों का इस्तेमाल, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना, वाहनों में जरूरत से अधिक भीड़ होना, वैध गति से अधिक तेज गाड़ी चलाना और थकान आदि होना है। शहरीकरण और सड़क यातायात बढ़ने के कारण सड़कों पर सुरक्षा के मुद्दे और इनके समाधानों पर गंभीरता से विचार हो रहा है। दुनिया में भारत में सबसे अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं में मर रहे हैं और इस कारण यह मुद्दा और भी गंभीर बन गया है। वर्ष 2011 में 4.97 लाख सड़क दुर्घटनाओं में 1.42 लाख से अधिक लोगों की जानें गईं। यह संख्या भारत में प्रति मिनट एक सड़क दुर्घटना और प्रत्येक चार मिनट में सड़क दुर्घटना से होने वाली मौत का आंकड़ा दर्शाती है। वर्ष 2012 में इन आंकड़ों में कुछ कमी आई, जिसमें 4.90 लाख सड़क दुर्घटनाओं में 1.38 लाख लोगों की जानें गईं। फिर भी यह संख्या विचलित करने वाली है। चालकों की गलती को लगभग 80 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाओं का जिम्मेदार पाया गया है, इसलिए उन्हें जागरूक बनाना और यह महसूस कराना आवश्यक है कि जब वे कानून/उपायों का उल्लंघन करते हैं तो वे सड़कों पर हत्यारे बन जाते हैं। सड़क सुरक्षा को राजनीतिक स्तर पर प्राथमिकता दी जा रही है। तदर्थ सड़क सुरक्षा गतिविधियों को सतत कार्यक्रमों में बदलने पर ध्यान दिया जा रहा है। राज्य क्षमता के अनुसार दीर्घकालीन और अंतरिम लक्ष्यों, नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करते समय वर्तमान सड़क सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के क्रमबद्ध मूल्यांकन की सिफारिश की गई है। इसके तहत उच्च स्तर पर सरकारी एजेंसियों, जैसे- परिवहन, पुलिस, स्वास्थ्य, न्याय और शिक्षा के वरिष्ठ प्रबंधन को, जो संभवतः अभी तक सक्रिय रूप से सम्मिलित नहीं हुआ है, को बहुस्तरीय रणनीति के अंतर्गत शामिल करना है। इसके अलावा सभी भागीदारों को सड़क सुरक्षा में अपना योगदान देना होगा। सड़क सुरक्षा की नीति को सुदीर्घ आधार पर लागू करने के लिए कई सरकारी विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन विभागों की जवाबदेही और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सड़क सुरक्षा पर सरकारी एजेंसियों में बेहतर तालमेल स्थापित करने, संबंधित राज्य में सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तथा सड़क दुर्घटनाओं में हताहतों की संख्या को न्यूनतम करने के लिए तकनीकी उपायों को लागू करने के लिए सभी राज्य सरकारों से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने को कहा गया है। इज्यों से अपनी सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने की कार्यनीति तैयार करने को भी कहा गया है। राज्यों से सड़क सुरक्षा की वार्षिक कार्यनीति के तहत पांच वर्ष के महत्वांकाशी और हासिल करने योग्य लक्ष्य तय करने को भी कहा गया है। इसके अंतर्गत मापन योग्य परिणाम, विकास के लिए पर्याप्त राशि का निर्धारण, प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन योग्य कार्यनीति तैयार करनी होगी। सभी राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों से उनके क्षेत्र में एक एजेंसी की पहचान करने और सड़क सुरक्षा कोष का निर्धारण करने तथा इस राशि का 50 प्रतिशत परिवहन नियमों की अवहेलना के दंड स्वरूप एकत्र करने को कहा गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए विभिन्न उपाय किये हैं। सरकार ने एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति भी मंजूर की है, जिसके तहत विभिन्न उपायों में जागरूकता बढ़ाना, सड़क सुरक्षा सूचना पर आंकड़ें एकत्रित करना, सड़क सुरक्षा की बुनियादी संरचना के अंतर्गत कुशल परिवहन अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करना तथा सुरक्षा कानूनों को लागू करना शामिल हैं। सड़क सुरक्षा के मामलों में नीतिगत निर्णय लेने के लिए भारत सरकार ने शीर्ष संस्था के रूप में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया है।

# आग के आगे लाचार सा दिख रहा अमेरिका...

अमेरिका का लॉस एंजेलिस झुलस रहा है। जंगल में धधक रही आग बेकाबू सी दिख रही है। 6 अलग-अलग जगहों पर आग धधक रही है- पैलिसेड्स, ईटन, हर्स्ट, लिडिया, केनेथ और हॉलिवुड हिल्स। लीडिया का तो 60 प्रतिशत जंगल जलकर राख हो चुका है। कुल मिलाकर 36 हजार एकड़ से ज्यादा का जंगल स्वाहा हो चुका है। 10 लोगों की मौत हो चुकी है। हॉलिवुड हिल तक आग पहुंच चुकी है। तमाम आलीशान मकान, स्टूडियो भी खाक हो चुके हैं। आग की भयावहता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि प्रत्यक्षदर्शी इसकी तुलना परमाणु बम विस्फोट से कर रहे हैं। दुनिया का सुपर पावर बेबस नजर आ रहा है। प्रकृति के रौद्र रूप के सामने आखिर किसका वश चलता है? अमेरिका हो या भारत, सब बेबस हैं। अभी सालभर भी नहीं हुए कि उत्तराखंड में कई दिनों तक धू-धूकर जलते रहे। लॉस एंजेलिस के जंगलों में आग की शुरुआत 7 जनवरी को हुई। अब तक यह आग कुल मिलाकर 36000 एकड़ जंगल को अपनी चपेट में ले चुकी है। 10 हजार से ज्यादा इमारते स्वाहा हो चुकी हैं। वहां के अधिकारी आशंका जता रहे हैं कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। आग को बुझाने की सारी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। तेज बवार और शुष्क मौसम आग को और धधका रही हैं। हर तरफ तबाही का मंजर है। वन्यजीव और वनसंपदा का नुकसान। घर-मकान,

स्टूडियो तबाह। 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। 1.8 लाख अन्य लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 1 लाख अन्य लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए चेतावनी दी जा चुकी है। एजेंसियों ने 1.9 करोड़ लोगों को आग के खतरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। यह इस महीने के अलावा पूरे फरवरी तक लागू रहेगा। लॉस एंजेलिस आग को एक्सपर्ट क्लाइमेट चेंज का दुष्परिणाम बता रहे हैं। तेल, कोयला और गैस के जलने से निकलने वाली वो गैसें जिन्से धरती गरम होती हैं, ने जंगल की आग को और खतरनाक बना दिया है। क्लाइमेट चेंज की वजह से कैलिफोर्निया में पतझड़/ठंड में बारिश के मौसम की शुरुआत को लेट कर दिया है। लॉस एंजेलिस तो जुलाई 2024 के बाद से ही बारिश की कमी का सामना कर रहा है। इलाका 150 वर्षों में दूसरे सबसे बड़े सूखे का सामना कर रहा है। इसी तरह दक्षिणी कैलिफोर्निया में 1 अक्टूबर से अब तक औसत बारिश 10 प्रतिशत की गिरावट हुई है। कई जगहों पर 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं बह रही हैं। इन स्थितियों ने आग को और विकराल कर दिया है। साल के इस समय लॉस एंजेलिस में तेज हवाएं सामान्य होती हैं लेकिन शुष्क मौसम और क्लाइमेट चेंज की वजह से जंगल की आग और ज्यादा खतरनाक हो रही है और

### अभिप्राय/धर्म/संस्था

# दुनिया की गति और हमारी प्रगति

2025 में जोर-आजमाइश के दो बड़े मौके बनेंगे। इस साल दिल्ली और बिहार विधानसभाओं के चुनाव हैं। दिल्ली का चुनाव फरवरी में ही हो जाएगा और बिहार में साल के आखिर में। दिल्ली में बीजेपी के सामने खंडित इंडिया गठबंधन होगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक-दूसरे से टकराने को तैयार हैं। राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण दिल्ली का प्रतीकात्मक महत्व है। यहां हार-जीत से बीजेपी को नफा-नुकसान नहीं होगा, पर यह प्रतिष्ठा की लड़ाई है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी चौथी बार जीतकर आई, तो वह राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण ताकत बनकर उभरेगी। वहीं यह कांग्रेस के लिए हैसियत बढ़ाने का एक अवसर है।

देखते ही देखते इक्कीसवीं सदी का 24वां साल गुजर गया और 25वां आ गया। जिस सदी को लेकर बड़े-बड़े सपने थे, उसके एक चौथाई साल 2025 में पूरे हो जाएंगे। किधर जा रही है दुनिया और कहाँ खड़े हैं हम? देश की करीब 145 करोड़ की आबादी में पांच से दस करोड़ लोगों ने 31 दिसंबर 2024 की रात नए साल का जश्न मनाकर स्वागत किया। शायद इतने ही लोगों को नए साल के आगमन की जानकारी थी, पर वे जश्न में शामिल नहीं थे। इतने ही लोगों ने सुना कि नया साल आ गया और उन्होंने यकीन कर लिया। फिर भी 100 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे होंगे, जिन्हें किसी के आने और जाने की खबर नहीं थी। उनकी वह रात भी वैसे ही बीती जैसे हमेशा बीतती है—सर्द और अंधेरी। नया साल आपके लिए और मेरे लिए कैसा होगा, इसका पता लगाने के दो तरीके हैं। या तो किसी ज्योतिषी की शरण में जाएं या वैश्विक घटनाक्रम की गुत्थियों को समझने की कोशिश करें कि हम पर उनका क्या असर होने वाला है। 2020 में जनवरी माह में हमें पता नहीं था कि हम खतरे से घिरने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा कुछ लोगों को खबर थी कि चीन में कोई बीमारी फैली है। लेकिन दो-तीन महीनों के भीतर हमने उस बीमारी को भारत में, और फिर अपने आसपास प्रवेश करते देख लिया।

मौसम, हवा, जलवायु, युद्ध और बीमारियों का जब असर होता है, तब सबके सिर चढ़कर बोलता है। अमीर—गरीब, छोटे—बड़े, गोरे—काले व सारे धार्मिक—सांस्कृतिक भेद एक साथ मिट जाते हैं। बहरहाल बदलते साल की बैलेंस—शीट पर कुछ बातें दर्ज होती जाती हैं, जिनसे पता लगता है कि गुजरे वक्त ने हमें क्या दिया व क्या छीना, और नया साल हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है।

देश की खोज—खबर बताने वाले मीडिया की मानें, तो सबसे बड़ा मसला राजनीति है। राष्ट्रीय राजनीति में करीब दस साल तक कतानी एकतरफा रहने के बाद पिछले साल सीधे मुकाबलों की ओर मुड़ी। देश में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा क्षेत्रीय दलों के रूप में एक तीसरी राजनीतिक ताकत और है। बीजेपी के विजय—रथ से कांग्रेस के अलावा इन्हें भी अपने अस्तित्व की फिक्र होने लगी। साल 2023 में इंडिया गठबंधन बन जाने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी जगहों पर सीधे मुकाबले हुए।

लोकसभा चुनाव में झटका लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में वापसी करके इंडिया गठबंधन को राजनीतिक जवाब दे दिया है। अब 2025 में जोर—आजमाइश के दो बड़े मौके बनेंगे। इस साल दिल्ली और बिहार विधानसभाओं के चुनाव हैं। दिल्ली का चुनाव फरवरी में ही हो जाएगा और बिहार में साल के आखिर में। दिल्ली में बीजेपी के सामने खंडित इंडिया गठबंधन होगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक-दूसरे से टकराने को तैयार हैं। राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण दिल्ली का प्रतीकात्मक महत्व है। यहां हार—जीत से बीजेपी को नफा—नुकसान नहीं होगा, पर यह प्रतिष्ठा की लड़ाई है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी चौथी बार जीतकर आई, तो वह राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण ताकत बनकर उभरेगी। वहीं यह कांग्रेस के लिए हैसियत बढ़ाने का एक अवसर है।

इस साल 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे। चूंकि बीजेपी ने 75 साल से ऊपर के लोगों को मार्गदर्शक बनाना शुरू कर दिया है, इसलिए मोदी—विरोधी



सवाल करेंगे। अरविंद केजरीवाल पृष्ठ चुके हैं कि क्या मोदीजी मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे? फिलहाल मोदी के बगैर बीजेपी की कल्पना संभव नहीं है। नए साल में बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। कई नाम उभर रहे हैं, पर माना जा रहा है कि जो भी होगा संघ का विश्वस्त होगा। अफवाहें हैं कि संघ और बीजेपी के बीच खिंचाव है, पर सच यह है कि हरियाणा और महाराष्ट्र की विजय के पीछे संघ का सक्रिय सहयोग रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के कुछ बयान मुख्यधारा के हिंदुत्व से मेल नहीं खा रहे, पर यह इतना अविचारित नहीं है, जितना लोग समझ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का यह शताब्दी वर्ष है। 1925 में विजया दशमी के दिन डॉ. केशव हेडगेवार ने संघ की स्थापना की थी। उस साल विजया दशमी 27 सितंबर को थी। इस साल 26 दिसंबर को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भी 100 वर्ष पूरे होंगे। संघ ने शताब्दी-वर्ष में अपनी शाखाओं की संख्या एक लाख करने का लक्ष्य रखा है, जिसका असर राजनीति में दिखेगा। संघ के 2025 के एजेंडा में सामाजिक समरसता भी शामिल है।

इंडिया गठबंधन के सामने नए साल में अपने आप को बचाए रखने और सहयोगियों को जोड़े रखने की चुनौती है। इसकी धुरी कांग्रेस को भी अपने आप को संगठनात्मक रूप से मजबूत करना होगा। पिछले साल हरियाणा और महाराष्ट्र में मिली विफलताओं के बाद गठबंधन के कुछ सहयोगियों ने कहना शुरू कर दिया है कि नेतृत्व हमें सौंपो। यह मांग करने वालों में तुणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी सबसे आगे हैं। इन बातों से बिहार चुनाव के दौरान सीट बंटवारे में कांग्रेस दबाव में रहेगी।

इस साल दो कानूनों पर राष्ट्रीय बहस शिद्दत से चलेगी। एक, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक और दूसरा, एक देश, एक चुनाव कानून। दोनों संसदीय समितियों के पास हैं। पर सबसे बड़ा कार्यक्रम है जनगणना का। लंबे समय से विलंबित जनगणना इस साल शुरू होने की संभावना है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में महत्वपूर्ण डेटा अंतराल दूर करना चाहेंगे। एक दशक में एक बार होने वाली जनगणना 2021 में पूरी होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हो गई। जनगणना से आर्थिक आंकड़ों, मुद्रास्फीति और रोजगार अनुमानों सहित कई अन्य सांख्यिकीय सर्वेक्षणों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इनमें से ज्यादातर डेटा सेट 2011 में जारी जनगणना पर आधारित हैं। जनगणना के प्रश्न ने राजनीतिक शक्ल भी धारण कर ली है। विरोधी दल जाति—जनगणना की बात कर रहे हैं, वहीं बीजेपी विपक्ष के इस एजेंडे को विभाजनकारी बताते हुए अपनी मुहिम जारी रख सकती है। पिछले साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देशभर में जाति जनगणना की मांग उठाई और आरक्षण के लिए

# मिटी चीफ

# हमारी प्रगति

50 फीसदी की कृत्रिम—सीमा को तोड़ने का आह्वान किया था। इस बीच, भाजपा ने अपने मूल वैचारिक मुद्दों में सामाजिक न्याय को भी जोड़ लिया है। पहले जातिगत मुद्दे क्षेत्रीय दलों जैसे बसपा, सपा, जेडीयू, राजद, लोजपा, रिपब्लिकन पार्टी आदि के अधिकार क्षेत्र में थे। इस मुद्दे पर कांग्रेस का फोकस बढ़ने के कारण पिछले एक साल में इसमें निर्णायक बदलाव आया है। जाति, आरक्षण और बीआर अंबेडकर की विरासत जैसे मुद्दों का वैचारिक दायरा इस साल और बढ़ेगा। दुनिया के सामने सबसे ज्यादा दबाव वाले मुद्दे तेजी से विकसित हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के पर्यावरणीय प्रभाव तेजी से बढ़ रहे हैं और लाखों लोगों के स्वास्थ्य और आजीविका को खतरा पैदा कर रहे हैं। तकनीकी विकास के बावजूद, उनके लिए कोई सुरक्षा कवच नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) रखा है। उसकी समय—सीमा से पांच साल पहले, दुनिया लक्ष्य से काफी दूर है। एक नजर 2025 के लिए निर्धारित सबसे प्रतीक्षित शिखर सम्मेलनों पर डालें कि क्या इस साल हम बेहतर दुनिया बनाने की दिशा में बढ़ पाएंगे। जनवरी में दावोस के विश्व आर्थिक मंच की बैठक में बिजनेस, सरकारों और नागरिक समाज के वैश्विक नेता मिल-बैठकर इन सवालों पर विचार करेंगे। दूसरी तरफ दुनिया के सात अमीर देशों के ग्रुप ऑफ सेवन (जी-7) का शिखर सम्मेलन कनाडा के रॉकीज में होगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण महासागर अत्यधिक मात्रा में गर्मी सोख रहे हैं, जो जैव विविधता के लिए एक गंभीर खतरा है। इस सिलसिले में भूमध्यसागर के तट पर फ्रांस और कोस्टा रिका की सह-मेजबानी में 2025 का संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन (यूएनओसी3) होगा।

सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) की 80वीं बैठक होगी। दुनिया के इस सबसे बड़े वार्षिक सम्मेलन में विस्थापन, संघर्ष, गरीबी, भुखमरी और सतत विकास के 2030 एजेंडा पर बातें भी होंगी, जो बुरी तरह से पटरी से उतर गए हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की तीसवीं बैठक, जिसे कॉप-30 के नाम से जाना जाएगा, ब्राजील में होगी। कॉप-29 के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद यहां काफी उम्मीदें होंगी। ऊर्जा भंडारण और कार्बन बाजारों पर किए गए समझौतों के बावजूद, विकासशील देशों को धनी देशों की ओर से धन देने का आश्वासन पूरा हुआ नहीं है। जी-20 का शिखर सम्मेलन इस साल पहली बार अफ्रीकी देश में होगा। पिछले साल अफ्रीकी संघ के इसमें शामिल होने के बाद यह शिखर सम्मेलन जोहानेसबर्ग में होगा। साल 2024 में जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला ब्राजील इस साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। शिखर सम्मेलन में अपने चार नए सदस्यों और तेरह भागीदार देशों का दूसरी बार स्वागत किया जाएगा और संभवतः इस समूह का और विस्तार करने पर विचार किया जाएगा।

अमेरिका का लॉस एंजेलिस झुलस रहा है। जंगल में धधक रही आग बेकाबू सी दिख रही है। 6 अलग-अलग जगहों पर आग धधक रही है- पैलिसेड्स, ईटन, हर्स्ट, लिडिया, केनेथ और हॉलिवुड हिल्स। लीडिया का तो 60 प्रतिशत जंगल जलकर राख हो चुका है। कुल मिलाकर 36 हजार एकड़ से ज्यादा का जंगल स्वाहा हो चुका है। 10 लोगों की मौत हो चुकी है। हॉलिवुड हिल तक आग पहुंच चुकी है। तमाम आलीशान मकान, स्टूडियो भी खाक हो चुके हैं। आग की भयावहता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि प्रत्यक्षदर्शी इसकी तुलना परमाणु बम विस्फोट से कर रहे हैं। दुनिया का सुपर पावर बेबस नजर आ रहा है। प्रकृति के रौद्र रूप के सामने आखिर किसका वश चलता है? अमेरिका हो या भारत, सब बेबस हैं। अभी सालभर भी नहीं हुए कि उत्तराखंड में कई दिनों तक धू-धूकर जलते रहे। लॉस एंजेलिस के जंगलों में आग की शुरुआत 7 जनवरी को हुई। अब तक यह आग कुल मिलाकर 36000 एकड़ जंगल को अपनी चपेट में ले चुकी है। 10 हजार से ज्यादा इमारते स्वाहा हो चुकी हैं। वहां के अधिकारी आशंका जता रहे हैं कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। आग को बुझाने की सारी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। तेज बवार और शुष्क मौसम आग को और धधका रही हैं। हर तरफ तबाही का मंजर है। वन्यजीव और वनसंपदा का नुकसान। घर-मकान,

अभी जिस तरह की तबाही से अमेरिका दो-चार हो रहा है, कुछ वैसी ही तबाही पिछले साल भारत में भी मची थी। अप्रैल 2024 में उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी थी। अल्मोड़ा के जंगलों में तो 41 दिनों तक आग धधकती रही थी। 10 लोगों की मौत हुई थी। सैकड़ों एकड़ जंगल स्वाहा हो गए थे। 6 मई 2024 की पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 1 नवंबर 2023 से 5 मई 2024 तक उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की कुल 575 घटनाएं दर्ज हुई थीं जिससे करीब 690 हेक्टेयर यानी 1705 एकड़ क्षेत्र प्रभावित हुआ था। आग लगने के वजहों में क्लाइमेट चेंज तो था ही, मानवीय लापरवाही ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी। उत्तराखंड के जंगलों में 2016 में भी भीषण आग लगी थी। तब अप्रैल और मई के बीच में करीब 1600 आग की घटनाएं दर्ज हुई थीं। 4538 हेक्टेयर यानी 11213 एकड़ जंगल स्वाहा हो गया था। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत के वन क्षेत्र का करीब 36 प्रतिशत हिस्सा आग के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। कैलिफोर्निया की आग को लेकर अधिकारियों ने पुष्टि की है कि आग में मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। अग्निशमन विभाग के जन संपर्क अधिकारी कार्लोस हेरेरा ने बताया कि ईटन में लगी आग से पांच लोगों की मौत हो गई। अग्निशमन विभाग की प्रवक्ता मागरिट स्टीवर्ट ने बताया कि पैरिफ्रिक पैलिसेड्स के पश्चिम में लगी आग में दो लोगों की मौत

हो गई है। वहीं तीन अन्य लोगों ने आग की चपेट में आकर जान गंवाई है। ईटन और पैलिसेड्स की आग के बीच 10,000 से अधिक इमारतें जल गईं। लॉस एंजेलिस अग्निशमन प्रमुख क्रिस्टिन क्राउले ने कहा कि पैलिसेड्स में 5,300 से अधिक इमारतें नष्ट हो गई हैं। ईटन फायर ने 5,000 से ज्यादा इमारतों को नष्ट कर दिया है। अपक्सरों का कहना है कि सर्वे के बाद यह संख्याएं बदल सकती हैं। वेस्ट हिल्स पड़ोस के पास नई आग के कारण अधिक लोगों को बाहर निकालना पड़ा। लॉस एंजेलिस फायर डिपार्टमेंट ने सैन फर्नांडो वैली में लॉस एंजेलिस के वेस्ट हिल्स इलाके के पास केनेथ फायर नामक आग के लिए आदेश जारी किए हैं। आग लगने के कारण इलाके को लोगों को तुरंत खाली करना पड़ा। लॉस एंजेलिस काउंटी के शेरिफ रॉबर्ट लूना ने कहा कि अधिकारियों ने गुरुवार रात से दोनों बड़ी आग के आसपास कर्फ्यू लागू करने की योजना बनाई, जो शाम छह बजे से अगले दिन सुबह छह बजे तक लागू रहेगा, लेकिन इसे लागू होने में समय लग सकता है। कर्फ्यू केवल उन क्षेत्रों पर लागू होगा जो आग से ज्यादा प्रभावित हैं। लॉस एंजिल्स यूनिफाइड के सभी स्कूल श्रुक्वार को बंद रखे गए। जिला अधीक्षक अल्बर्टो कार्वाल्हो ने कहा कि जब तक हालात नहीं सुधरते तब तक कक्षाएं शुरू नहीं

होंगी। यहां दो प्राथमिक विद्यालय नष्ट हो गए हैं और एक हाईस्कूल को काफी नुकसान पहुंचा है। हम उन कर्मचारियों की सहायता कर रहे हैं, जिन्होंने अपने घर खो दिए हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आग जारी रह सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि शुक्रवार के बाद भी खतरा खत्म नहीं होगा। हवाएं अगले सप्ताह की शुरुआत तक जारी रहेंगी। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अपने गृह राज्य कैलिफोर्निया में लगी आग के कारण अपने कार्यकाल की अंतिम विदेश यात्रा रद्द कर दी है। हैरिस ने 13 से 17 जनवरी तक सिंगापुर, बहरीन और जर्मनी की यात्रा की योजना बनाई थी। अधिकारियों का कहना है कि अग्निशमन दल ने पैलिसेड्स की आग पर कुछ हद तक काबू पा लिया है। गवर्नर गेविन न्यूसम ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेज हवाओं से भड़की आग पर काबू पाने के लिए चौबीस घंटे काम कर रहे हमारे बहादुर अग्निशमन कर्मियों को धन्यवाद। गवर्नर ने कहा कि तेजी से फैल रही आग से निपटने के लिए 900 से अधिक अग्निशमन कर्मी तैनात किए जाएंगे। वेस्ट हिल्स और कैलाबास के पास तेजी से फैल रही केनेथ फायर से लड़ने के लिए अब 900 अतिरिक्त अग्निशमन कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। मौसम और उसके प्रभाव के आंकड़े देने वाली निजी कंपनी एक््यूव्देर ने आग से नुकसान और आर्थिक क्षति

का अनुमान बढ़ाकर 135-150 अरब डॉलर कर दिया। पहले कंपनी ने 57 बिलियन डॉलर का नुकसान होने का अनुमान लगाया था। लॉस एंजेलिस में लगी आग को लेकर कनाडा के मंत्री ने कहा कि कनाडाई सैन्यकर्मी, उनके उपकरण और 250 अन्य अग्निशमन कर्मी अमेरिका की सहायता के लिए तैयार हैं। हरजीत सज्जन ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रीय अंतर-एजेंसी अग्नि केंद्र ने आग के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए अपने दो सीएल-415 स्कीमर एयरटैंकरों की मांग की है। राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि दक्षिणी कैलिफोर्निया के लोगों के लिए उनका संदेश है कि हम आपके साथ हैं। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब जबकि उनके कार्यकाल के दो सप्ताह से भी कम समय बचा है, तो यह ऐसा वादा है जिसे वह पूरा नहीं कर पाएंगे। रिपब्लिकन डॉनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद संभालेंगे।

हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और सिंगर पेरिस हिल्टन का घर भी कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग की वजह से खाक हो गया। मालिबू में अपने प्यारे घर को जलते देखने के बाद उनका दिल शीशे की तरह चकाटूर हो गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना दुख जाहिर किया। लॉस एंजिल्स में अपने घर जलने के बाद पेरिस हिल्टन ने अपने एक्स अकाउंस पर एक दुखद पोस्ट शेयर किया। उन्होंने एलए जंगल की आग के बाद अपने मालिबू घर की अभी की

स्थिति को दर्शाते हुए एक वीडियो भी शेयर किया। उन्होंने इसे सहन ना सके ऐसा दर्द बताया। अभिनेत्री और सिंगर पेरिस हिल्टन ने आगे घर में बिताए पलों को याद किया साथ ही उन लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाई, जिनका घर इस जंगल की आग में जलकर राख हो गया और वह इसे खोने के बाद दर्द से गुजर रहे हैं। पेरिस ने लिखा, हूमें यहां खड़ी हूं, जो कभी हमारा घर हुआ करता था। इसे देखने के बाद मेरे दिल का दर्द वास्तव में अवर्णनीय है, जब मैंने पहली बार खबर देखी, तो मैं पूरी तरह से सदमे में थी। मैं इसे समझ नहीं कर सकी, लेकिन अब, यहां खड़ी हूं और इसे देख रही हूं तो मेरी अपनी आंखों से। अब इसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिल लाखों टुकड़ों में बिखर गया हो। पेरिस ने आगे लिखा, यह घर सिर्फ मेरे रहने की जगह नहीं थी बल्कि यह वह जगह है, जहां हमने सपने देखे, हंसे, और एक परिवार के रूप में सबसे खूबसूरत यादें बनाईं। यह वजह जगह है, जहां फीनिक्स के छोटे हाथों ने कला बनाई थी। इस घर के हर एक कोने में प्यार और जीवन भरा हुआ था। इसे राख में तब्दील होते देखना... इस हादसे को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। यह जानकर मेरा दिल और भी टूट गया है कि यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं है – यह सिर्फ दीवारें और छतें नहीं हैं। यह यादें ही हैं जो बर्नी मेरा घर, ये तस्वीरें, यादें, हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।



# कटनी के जंगल में तेंदुआ दिखने से मची सनसनी

## बांधवगढ़ नेशनल पार्क की टीम ने किया सफल रेस्क्यू

**सुनील यादव । सिटी चीफ** कटनी, कटनी जिले के विजयराधवगढ़ वन परिक्षेत्र कांटी पुरैनी जंगल में अचानक एक तेंदुआ दिखाई देने से इलाके में सनसनी फैल गई ग्रामीणों ने तुरंत की इसकी सूचना वन विभाग को दी सूचना मिलते ही मौके पर वन अमला पहुंच गया और तेंदुए के रेस्क्यू के लिए बांधवगढ़ नेशनल पार्क के रेस्क्यू टीम सूचना दी। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मौके पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क की रेस्क्यू टीम के साथ डॉक्टर भी पहुंच गए और कड़ी मस्कत के बाद करीबन एक साल के तेंदुआ का रेस्क्यू कर पकड़ा गया। तेंदुए के आंख के चोट के निशान हैं वाह कमजोर स्थिति है जिसका मौके पर ही इलाज किया जा रहा है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क के डॉक्टर राजेश तोमर ने बताया कि तेंदुए की उम्र



7 से 8 माह के बीच की है तब तेंदुए का रेस्क्यू किया गया उसकी हालत नजुग थी जिसे साधारण जाल से पकड़ कर पिंजरे में रखा गया है और इस तेंदुए का मौके पर ही इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर ने यह भी बताया कि

रेस्क्यू किए गए तेंदुए को मुकुंदपुर ले जाया जाएगा जहां इस तेंदुए का सही तरह से इलाज किया जाएगा। वही वन विभाग अधिकारी विवेक जैन यह बताया कि कल शाम को उन्हें सूचना मिली थी कि रहवासी इलाके में

पकड़े गए तेंदुए का मूमेंट है और ग्रामीण दहशत में है। जिस सूचना पर वह कल रात से ही तेंदुए पर नजर बनाए हुए थे और दोपहर को बांधवगढ़ नेशनल पार्क की टीम मौके पर पहुंच तेंदुए का रेस्क्यू किया।

## उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी अब तक न्यूनतम वेतन की बढ़ी दरों से भुगतान आदेश जारी न होने से प्रदेश भर में भारी रोष

### सीटू ने प्रमुख सचिव ( श्रम) व श्रमायुक्त को न्यायालय की अवमानना का नोटिस दिया

**श्रीनिवास मिश्रा । सिटी चीफ** भोपाल, माननीय म. प्र. उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ द्वारा गत 3 दिसम्बर 2024 को न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों के भुगतान पर लगे स्थगन को समाप्त कर दिए जाने के एक माह बाद भी म. प्र. शासन की ओर से बढ़ी हुई दरों से वेतन भुगतान हेतु कोई निर्देश जारी नहीं हुए है । एक माह से ज्यादा समय होने के बाद भी निर्देश जारी न करने पर सेन्टर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू) के प्रदेश महासचिव प्रमोद प्रधान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बाबूलाल नागर ने कल 6 जनवरी 2025 को प्रमुख सचिव (श्रम) व श्रमायुक्त म. प्र. को नोटिस दे कहा है कि अगर तुरंत आदेश जारी नहीं हुए तो माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई सीटू की ओर से प्रारंभ की जाएगी। (दिये गये नोटिस की प्रति आपके सूचनार्थ संलग्न है ) ज्ञातव्य हो कि सीटू इस कानूनी लड़ाई में पक्षकार के रूप में शामिल है। सीटू प्रदेश अध्यक्ष रामविलास गोस्वामी व महासचिव प्रमोद प्रधान ने मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि माननीय उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बाद भी बढ़ी हुयी दरों से भुगतान सम्बन्धी निर्देश जारी न करना प्रदेश के 25 लाख से ज्यादा श्रमिकों व कर्मचारियों के जीवन पर न सिर्फ कुटाराघात है बल्कि नियोजकों के हित साधने की बेशर्मीपूर्वक कारगुजारी है। सीटू नेताओं ने स्पष्ट किया कि सीटू ने श्रमिकों के हितों के संरक्षण के

लिए प्रमुख सचिव (श्रम) व श्रमायुक्त म. प्र. को यह कानूनी नोटिस देने के साथ समूचे प्रदेश में मैदानी संघर्ष भी तेज करने का निर्णय लिया है। सीटू नेताओं ने कहा कि प्रदेश स्तर पर अन्य श्रमिक व कर्मचारी संगठनों को एकजुट कर संघर्ष तेज करने हेतु भी सीटू ने पहल करने का निर्णय लिया है। सीटू जिला समिति के.जे.एस. सीमेंट मेहर के नेतागण, अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह महामंत्री राजेश मिश्रा कार्यवाहक अध्यक्ष निलेश गुप्ता उपाध्यक्ष रणजीत सिंह कोषाध्यक्ष संदीप सिंह भारत द्विवेदी शैलेंद्र सिंह पुष्पराज सिंह एवं समस्त यूनियन के पदाधिकारी गण ने उपरोक्त विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री प्रदेश के खजाने से सैकड़ों करोड़ खर्च कर इन्वेस्टर मीट आयोजित कर खरबों-खरब की जमीनें, प्राकृतिक संसाधन आदि कॉर्पोरेट्स के हवाले करने के साथ उन्हे करों में अकल्पनीय रियायतें भी दे रहे हैं, पर वही मुख्यमंत्री प्रदेश के लाखों मजदूरों व कर्मचारियों का वैधानिक न्यूनतम वेतन की वृद्धि तक को रूकवाए हुए है । नेताओं ने प्रदेश के मजदूरों व कर्मचारियों से अपील की है वे प्रदेश सरकार के इस मजदूर विरोधी रवैये के खिलाफ सीटू के मैदानी संघर्ष में भागीदारी करें। विज्ञप्ति में बताया गया है कि श्री शीघ्र ही सीटू राज्य स्तर पर मैदाने व कानूनी लड़ाई की विस्तृत योजना घोषित करेगी।

## सहारनपुर जिले में 33330 मतदाता बढ़े

### जिले में युवा मतदाताओं की संख्या 35260 है



**गौरव सिंघल । सिटी चीफ** (उत्तर प्रदेश) सहारनपुर, सहारनपुर जिले में 53169 नए मतदाता बनाए गए हैं और 19839 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इस तरह से कुल 33330 मतदाता बढ़े हैं। जिले में अब कुल मतदाताओं की संख्या 2616651 हो गई है। जिनमें 1383115 पुरुष और 1233437 महिलाएं हैं। 99 थर्ड जेंडर हैं।विधानसभावार मतदाताओं की संख्या अब इस प्रकार है। सहारनपुर नगर में मतदाताओं की कुल संख्या 454620 है। उत्तर प्रदेश की पहले नंबर की विधान सभा सीट बेहट में मतदाताओं की संख्या 376433 है। सहारनपुर देहात के मतदाताओं की संख्या 373500 है।

रामपुर मनिहारन आरक्षित सीट के मतदाताओं की संख्या 318969 है और देवबंद विधानसभा सीट के मतदाताओं की संख्या 346747 है। ये सभी पांचों विधान सभा क्षेत्र सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। जिले की दो अन्य विधान सभा गंगोह में मतदाताओं की संख्या अब 386425 हो गई है और नकुड़ में 359957 मतदाता हो गए हैं। ये दोनों सीटें कैराना संसदीय क्षेत्र में आती हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक पूरे सहारनपुर जनपद में 18 से 19 साल के युवा मतदाताओं की संख्या 35260 है। इनमें 19805 पुरुष और 15451 महिला मतदाता है। 4 थर्ड जेंडर हैं।

**गौरव सिंघल । सिटी चीफ** (उत्तर प्रदेश) सहारनपुर, स्वैच्छिंग संगठन राजसी डेवलपमेंट एण्ड रिसर्च संस्थान द्वारा संचालित बाल गृह (बालिका) में निवासरत बालिकाओं को लाल सखी संस्था द्वारा प्रोजेक्ट स्किल कनेक्ट मेरा हुनर, मेरी पहचान के अंतर्गत सिलाई, कढ़ाई व बुनाई का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जिससे बालिकाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। बालगृह (बालिका) में निवासरत बालिकाओं को फैशन डिजाइनिंग के प्रशिक्षण हेतु पहले

बैच में कुल 22 बालिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने पर बालिकाओं को जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए सम्मानित किया गया तथा बालिकाओं का उत्साहवर्धन करते हुए बालिकाओं को प्रशिक्षण में अधिक से अधिक प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। डीएम मनीष बंसल ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु 05 सिलाई मशीन प्रदान करने का आश्वासन दिया गया तथा बालिकाओं के

**गौरव सिंघल । सिटी चीफ** (उत्तर प्रदेश) सहारनपुर, जनपद में 466 इकाइयों के लिए उद्यमियों ने समझौतों पर दस्तखत किए थे जिनमें से पिछले वर्ष 24 फरवरी को 131 इकाइयों का शिलायास हो चुका था उनमें से 67 इकाइयों ने काम शुरू कर दिया है और बाकी इकाइयां प्रक्रियाधीन हैं। जिनके अगले वर्ष तक शुरू हो जाने की उम्मीद है। उद्योग विभाग के उपायुक्त वीरेंद्र कुमार कौशल ने बताया कि उद्यमियों को मशीन की लागत पर 30 फीसद एकमुश्त अनुदान दिया जा रहा है और नई इकाइयों को लगाने में भूमि की

# कटनी में आईसीटीएम समिति की हुई बैठक

डिजिटल सुरक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण की रणनीतियों पर चर्चा

**सुनील यादव । सिटी चीफ** कटनी, मध्य प्रदेश के लिए यह एक ऐतिहासिक पहल रही, जब राज्यसभा की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रबंधन आईसीटीएम पर संसदीय स्थायी समिति ने पहली बार कटनी शहर का दौरा किया और अपनी बैठकों को सफलतापूर्वक संपन्न किया समिति की अध्यक्षता निरंजन बिस्सी अध्यक्ष, आईसीटीएम एवं सांसद, राज्यसभा द्वारा की गई, जिसमें सार्वजनिक सेवाओं को सशक्त बनाने और नागरिकों के डेटा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तकनीकी प्रगति के उपयोग पर मुख्य रूप से जोर दिया गया। इसमें गुलाम अली सांसद, राज्यसभा तथा डॉ. कुशल पाठक सांयुक्त सचिव, राज्यसभा सहित अन्य सदस्य भी सम्मिलित हुए। पहली बैठक के दौरान केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रतिनिधियों ने डाक विभाग, म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्थानीय पुलिस, स्थानीय प्रशासन और कॉमन सर्विस सेंटर के अधिकारियों के साथ मिलकर नागरिकों के डेटा की सुरक्षा एवं साइबर धोखाधड़ी से निपटने के अहम मुद्दों पर चर्चा की। डिजिटल अपराधों के तेजी



से बढ़ते खतरे पर जोर देते हुए प्रतिभागियों ने वित्तीय संस्थानों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता को रेखांकित किया, जिससे क्षेत्र में एक मजबूत डिजिटल सुरक्षा ढांचा तैयार हो सके।दूसरी बैठक में राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, स्थानीय प्राधिकरणों और विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के अधिकारियों ने एक व्यापक डिजिटल रिपॉजिटरी बनाने की संभावना पर विचार-विमर्श किया, जो कटनी में पाए जाने वाले प्राचीन मूर्तियों और शिल्पों को संरक्षित और लोकप्रिय बना सके। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र की

समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना और नवीन प्रौद्योगिकी समाधानों के माध्यम से जागरूकता व पर्यटन को बढ़ावा देना है। समिति ने यह विशेष रूप से रेखांकित किया कि नए नवाचारों को अपनाने और मजबूत डिजिटल सुरक्षा उपायों को लागू करने के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है, ताकि आधुनिकीकरण की रफ्तार में सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता न हो।इस प्रकार, समिति छोटे शहरी केंद्रों जैसे कटनी पर ध्यान केंद्रित करके प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करती है और समावेशी विकास एवं दीर्घकालिक स्थिरता के लिए एक मिसाल कायम करती है।

## कार्यक्रम आयोजक एवं जुगाडू एडवरटाइजिंग के फाउंडर अमन मिश्रा ने भोपाल में उपमुख्यमंत्री से की मुलाकात

**उमेश कुशवाहा । सिटी चीफ** सतना, भोपाल प्रवास के दौरान मध्यप्रदेश क्रिएटर्स अवार्ड 2025 के संदर्भ में मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला से कार्यक्रम के आयोजक एवं जुगाडू एडवरटाइजिंग के फाउंडर अमन मिश्रा उर्फ जुगाडू अमन एवं उनकी टीम ने उनके वी 9 चार इमली स्थित कार्यालय में मुलाकात कर कार्यक्रम की जानकारी एवं आमंत्रण दिया। उपमुख्यमंत्री द्वारा इस कार्यक्रम के आयोजक अमन मिश्रा को बधाई एवं शुभकामनाएं दिया ,साथ ही प्रदेश के सबसे बड़े क्रिएटर्स कार्निवल का आमंत्रण स्वीकार किया। श्री मिश्रा ने उपमुख्यमंत्री को जानकारी देते हुए बताया 2024 में उनके संयोजन में विन्ध्य क्रिएटर्स अवार्ड का आयोजन किया गया था। जिसमें कई जिलों के 400 से ज्यादा क्रिएटर्स ने भाग लिया था, इस वर्ष इसे बड़ा स्वरूप देते हुए मध्यप्रदेश क्रिएटर्स अवार्ड का आयोजन 03 फरवरी 2025 को सतना में किया जा रहा है। जो प्रदेश का सबसे बड़ा क्रिएटर्स कार्निवल होगा जिसमें मध्यप्रदेश उत्तरप्रदेश छत्तीसगढ़ के 1000 से ज्यादा क्रिएटर्स एक छत के नीचे होंगे, एक बड़े संदेश के साथ इस



कार्यक्रम को बड़ा स्वरूप दिया जा रहा है। पूरे कार्यक्रम में उन तमाम चर्चित चेहरे को आमंत्रित किया गया है जिनके माध्यम से लाखों लोगों तक आसानी से कम समय में संदेश दिया जा सकता है, लोकप्रियता के अपने अलग अलग पैमाने है जिसमे वर्तमान समय में सोशल मीडिया एक विशेष माध्यम बना हुआ है जहाँ पर आप अपने हुनर का प्रदर्शन आसानी से कर सकते हैं, इस कार्यक्रम में सभी क्रिएटर्स को मंच देके डिजिटल इंडिया को और मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है, यह एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ

सामाजिक, राजनैतिक व्यावसायिक, एवं कला क्षेत्र के सभी लोगो का संगम एक छत के नीचे किया जा रहा है जिससे प्रदेश के विकास को बढ़ाने में इस कार्यक्रम का योगदान हो। श्री मिश्रा ने बताया विन्ध्य क्रिएटर्स अवार्ड का आयोजन होने के बाद सैकड़ो क्रिएटर्स को रोजगार मिलना शुरू हुआ है उसी प्रकार मध्यप्रदेश क्रिएटर्स अवार्ड के बाद इस इस कड़ी को और बड़ा करते हुए आगे बढ़ाया जा सके ऐसा प्रयास किया जा रहा है। साथ विपिन सिंह ,अमृता सिंह ,सुमित गुप्ता ,दिव्यांश शर्मा रहे।

## बालगृह बालिका में निवासरत फैशन डिजाइनिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी बालिकाओं को जिलाधिकारी ने दिया प्रमाण पत्र



उज्ज्वल भविष्य की कामना की गयी। संस्था लाल सखी की संस्थापक एवं डायरेक्टर प्रीती जांगड़ा द्वारा भी बालिकाओं के जीवन में बदलाव लाने के उद्देश्य से बालिकाओं को मन लगाकर ट्रेनिंग में प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे बालिकाएं स्वयं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होकर उद्यमी बन सके। कार्यक्रम के दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी अभिषेक कुमार पाण्डेय बालगृह (बालिका) की प्रभारी अधीक्षिका के साथ-साथ समस्त स्टाफ व संस्था की बालिकाएं उपस्थित रही।

## एमओयू साइन वाली 466 में से 67 औद्योगिक इकाइयों ने काम शुरू किया, बाकी प्रक्रियाधीन



ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इन सभी इकाइयों में 11788 करोड़ का निवेश होना था। उन सबकी क्रियाशील होने पर 50 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। लेकिन अब जो 67 इकाइयां शुरू हुई हैं उनसे 3000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया होगा। अभी जो इकाइयां शुरू हुई हैं उनमें सबसे ज्यादा इकाइयां माइक्रो स्माल मीडियम एंटर प्राइजेज की हैं यानि एमएसएमई जिनमें 548 करोड़ का निवेश हुआ है और 1100 लोगों को रोजगार मिलेगा। 15 इकाइयां पशु पालन विभाग से संबंधित हैं।



# देश के अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा - भगत सिंह वर्मा

## भाकियू वर्मा का जत्था खनोरी बॉर्डर के लिए हुआ रवाना

**गौरव सिंघल । सिटी चीफ**(उत्तर प्रदेश) सहरानपुर । देवबंद, ग्राम गंगदासपुर जट में भारतीय किसान यूनियन वर्मा व पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा की बैठक करके किसानों का जत्था राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा के नेतृत्व में खनोरी बॉर्डर पंजाब के लिए रवाना हो गया है। बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन वर्मा व पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने कहा कि कृषि प्रधान देश भारतवर्ष में भाजपा की केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश का अन्नदाता किसान बर्बादी के कगार पर है। पिछले 11 महीने से खनोरी बॉर्डर शंभू बॉर्डर डबवाली बॉर्डर पर देश के लाखों किसान हजारों ट्रैक्टर-ट्रालियों के साथ हाईवे पर धरना दिए हुए हैं। खनोरी बॉर्डर पर देश के ईमानदार किसान नेता सरदार जगजीत सिंह डब्लेवाल पिछले 44 दिन से किसानों की समस्याओं को लेकर आमरण अनशन पर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने



विरोध प्रकट करते हुए कहा कि दिल्ली में केंद्र की मोदी सरकार किसान विरोधी और किसानों के प्रति उदासीन है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी गलती स्वीकारते हुए कहा था कि हम जल्द ही एमएसपी को गारंटी कानून बनाएंगे और

किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। किसानों की आय दोगुनी तो क्या आधी भी नहीं रह गई है। किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य तो दूर लागत मूल्य भी सरकार नहीं दिला पा रही है। जिसके कारण आज देश के अन्नदाता

किसानों पर 23 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है और किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। भगत सिंह वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को जल्द ही किसान नेताओं से बात करके देश हित में किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाना चाहिए। एम एस पी को गारंटी कानून बनाना चाहिए। सरकार की गलत नीति के कारण कर्जबंद हुए किसानों के सभी कर्ज समाप्त होने चाहिए। डॉ एम एस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना चाहिए। देश के अन्नदाता किसानों की एक निश्चित आय करने के लिए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बराबर आय करने के लिए राष्ट्रीय आय आयोग का गठन करना चाहिए। 58 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग किसानों और मजदूरों को ?10000 प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन दिलानी चाहिए। गन्ना देश और सभी राज्यों की आर्थिक रीढ़ है। गन्ना किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य ?700 कुंतल तत्काल

घोषित करना चाहिए। चीनी मिलों से गन्ना किसानों को तत्काल गन्ना भुगतान व ब्याज दिलाना चाहिए। देश के अन्नदाता किसान दिल्ली में सत्ता में भागीदारी नहीं करना चाहते हैं। किसानों को तो अपनी समस्या हल होनी चाहिए। लोकतंत्र शासन में किसानों को अपनी बात दिल्ली जाकर कहने का हक होना चाहिए। इस प्रकार सड़कों पर अवरोध करके किसानों को दिल्ली जाने से रोकना अंग्रेजी हुकूमत की याद दिलाता है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय सलाहकार हाफिज मुर्तजा त्वागी ने कहा कि किसानों के साथ अन्याय किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसान अपने हकों के लिए बराबर लड़ते रहेंगे। बैठक का संचालन करते हुए भारतीय किसान यूनियन वर्मा के राष्ट्रीय सलाहकार रजत शर्मा ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं। प्रधानमंत्री मोदी को और दिल्ली में बैठे हुए बड़े नेताओं को अन्नदाता किसानों से वार्ता करके उनकी

समस्या को तत्काल हल करना चाहिए। खेती किसानी और गांव को बचाने के लिए लुटियंस जोन दिल्ली में बैठे हुए नेताओं को ठोस कदम उठाने चाहिए। किसान बचेगा तो देश बचेगा। बैठक में भारतीय किसान यूनियन वर्मा के प्रदेश महामंत्री आसिम मलिक, प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद जहीर तुर्की, प्रदेश सचिव ऋषिपाल गुर्जर, प्रदेश संगठन मंत्री धर्मवीर चौधरी, मंडल मीडिया प्रभारी दुष्यंत सिंह, जिला उपाध्यक्ष वसीम जहीरपुर, जिला संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह एडवोकेट, जिला मंत्री महबूब हसन, पदम सिंह, प्रदीप कुमार, जोगेंद्र सिंह, विपिन कुमार, दीपक चौधरी, जगपाल सिंह, रविंद्र सिंह, गौरव शर्मा, महेंद्र सिंह, अभिषेक चौधरी, सुमित वर्मा, अमित कुमार, आकाश चौधरी, हिमांशु, सुरेश कुमार आदि ने भाग लिया। बैठक के बाद किसानों का जत्था राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा के नेतृत्व में खनोरी बॉर्डर पंजाब के लिए रवाना हो गया।

## मुख्यमंत्री के निर्देशों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हेलमेट एवं कार सवार को सीटबेल्ट लगाना अनिवार्य निर्धारित समय पर नहीं पहुंचने पर अब होगी कड़ी कार्रवाई

**राजीव खरे । सिटी चीफ** (छत्तीसगढ़) रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशों पर अब त्वरित अमल होने लगा है। कलेक्टर डा. गौरव सिंह ने आज कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में कलेक्ट्रेट के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समस्याओं को सुना। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दोपहिया वाहन चलाने के दौरान हेलमेट लगाने एवं कार सवार को सीटबेल्ट लगाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि विभागीय प्रमुख निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचें और कर्मचारियों के भी समय पर निर्धारित समय पर पहुंचना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने सभी विभागों के उपस्थिति रजिस्टर की जांच की और उपस्थिति की जांच की। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि अब समय पर कार्यालय नहीं पहुंचने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि कलेक्ट्रेट में पहुंचने वाले सभी आमजनों के साथ अधिकारी एवं कर्मचारी सहज व्यवहार रखें और कार्यालयों की साफ-सफाई भी



रखी जाए। कलेक्टर ने कहा कि महिला एवं पुरुष टायलेट की सफाई समय-समय पर की जाए। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 5.15 बजे सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच की जाएगी। अनुपस्थित मिलने पर संबंधित पर कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही प्रत्येक कार्यालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम की

पट्टिकाएं होना अनिवार्य है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी प्रत्येक सोमवार एवं गुरुवार को निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचकर आमजनों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप भी उपस्थित थे।

**गौरव सिंघल । सिटी चीफ** (उत्तर प्रदेश) नागल । सहरानपुर, मुस्लिम फंड ट्रस्ट देवबंद के महाप्रबंधक मरहूम हसीब सिद्दीकी की पुण्यतिथि पर आज मुस्लिम फंड ट्रस्ट देवबंद की ओर से नागल ब्रांच में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें डॉक्टरों ने सैकड़ों मरीजों की फ्री जांच करके उन्हें निःशुल्क दवाइयां दी नागल स्थित मुस्लिम फंड की ब्रांच में आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर का उद्घाटन मुस्लिम फंड देवबंद के प्रबंधक सुहेल सिद्दीकी ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर सुहेल सिद्दीकी ने कहा कि गरीब जरूरतमंद मरीजों की सेवा करना नेक काम है। इस महंगाई के दौर में गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना मानवता की सच्ची सेवा है। उन्होंने बताया कि मुस्लिम फंड और उसके अधीन संस्थाएं जनता की सेवा करने में हमेशा आगे रहती हैं। उन्होंने कहा कि महाप्रबंधक हसीब सिद्दीकी मरहूम की बरसी के अवसर पर यह निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी उसी सेवा का हिस्सा है। ब्रांच मैनेजर साजिद हसन ने बताया कि संस्था की ओर से समय-समय पर लोगों की भलाई



के लिए इस तरह के नेक काम किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज शिविर में डॉक्टर जावेद अली, डॉक्टर मोमिन, डॉक्टर शहादत और डॉक्टर शहरी परवीन ने मरीजों की शुगर, ब्लड प्रेशर

और ऑक्सीजन आदि की फ्री जांच करके उन्हें मुफ्त दवाइयां दी, साथ ही नजला, खांसी, बुखार आदी, डॉक्टर मोमिन, डॉक्टर को भी फ्री दवाइयां और बचाव हेतु जरूरी मशवरे दिए गए। इस

अवसर पर फैजी सिद्दीकी, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद इंतजार, इस्लाम प्रधान, मोहम्मद अयूब, हाफिज सलीम, मुबशिर, जमशेद, आमिर इस्लाम और शाहिद हसन आदि मौजूद रहे।

## NSCB मेडिकल कॉलेज 1975 बैच का स्वर्ण जयंती पुनर्मिलन भव्यता पूर्ण कार्यक्रम 11-12 जनवरी को होगा सम्पन्न..?

नरसिंहपुर नेता जी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर के इस समारोह में 81 पूर्व छात्र भाग लेंगे, जिनमें से 15 विदेशों से आ रहे हैं। सभी पूर्व छात्र 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, जिन्होंने 50 वर्षों की अपनी पेशेवर यात्रा में चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समारोह के मुख्य आयोजन कलचुरी रेजिडेंसी और एनएससीबी मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में किए जाएंगे। पुनर्मिलन का उद्देश्य 1975 बैच के पूर्व छात्रों को एक मंच पर लाना है, जहां वे अपने अनुभव साझा कर सकें और अपने मेडिकल करियर के सुनहरे दिनों को याद कर सकें। कार्यक्रम का उद्घाटन 11 जनवरी को औपचारिक सत्र से होगा, जिसमें मुख्य अतिथि और विशिष्ट वक्ता चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान की कहानियां साझा करेंगे। इसके बाद, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और कॉलेज के पुराने दिनों की यादें ताजा करने वाले सत्र होंगे। समारोह के दौरान पूर्व छात्र बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का भ्रमण भी करेंगे ( 13-14 जनवरी)। यह यात्रा न केवल उन्हें प्रकृति के करीब लाने का एक प्रयास है, बल्कि वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी उद्देश्य रखती है। इस यात्रा के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जाएगा। आयोजन समिति ने इस कार्यक्रम को भव्य और यादगार बनाने के लिए कई गतिविधियां और सत्रों की योजना बनाई है। कार्यक्रम में शामिल मुख्य गतिविधियां हैं- पुराने दोस्तों से मिलकर अनुभव साझा करना छात्रों और नए चिकित्सकों के साथ बातचीत मेडिकल कॉलेज के वर्तमान और



भविष्य पर चर्चा सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें संगीत और नाटक की प्रस्तुति होगी। समारोह की तैयारी में मुख्य भूमिका निभा रहे आयोजक हैं डॉ. विनोद गर्ग डॉ. प्रदीप कुमार कसार (पूर्व डीन) डॉ. कमल किशोर रीखारी डॉ. अजय सराफ डॉ. आलोक अग्रवाल डॉ. नरेंद्र खरे डॉ. मुरली अग्रवाल (पूर्व सीएमएचओ)। कार्यक्रम में

परिवारों को भी शामिल होने का अवसर मिलेगा, जिससे यह आयोजन और भी व्यक्तिगत और भावनात्मक बन जाएगा। एनएससीबी मेडिकल कॉलेज के 1975 बैच के यह पुनर्मिलन न केवल उनके दोस्ती और पेशेवर रिश्तों को मजबूत करेगा, बल्कि उनके योगदान और अनुभवों को नई पीढ़ी के साथ साझा करने का एक मंच भी बनेगा। आयोजकों

ने उम्मीद जताई है कि यह समारोह 1975 बैच की ऐतिहासिक यात्रा को और ऊंचाई पर ले जाएगा। समारोह का समापन 12 जनवरी की शाम को रात्रिभोज और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ होगा। इस पुनर्मिलन के जरिए पूर्व छात्र अपने कॉलेज के दिनों की सुनहरी यादों को फिर से जीने का अवसर प्राप्त करेंगे।

## हर साल 40 करोड़ रुपए का राजस्व देता है नीमच का उप पंजीयक कार्यालय, पर लोगों के बैठने तक की व्यवस्था नहीं

-बारिश, ठंड और गर्मी में परेशान होते हैं क्रेता-विक्रेता, शौच के लिए पड़ता है भटकना नीमच। पंजीयक कार्यालय नीमच शासन को हर साल करीब 40 करोड़ रु का राजस्व देता है, लेकिन विडंबना है कि जिले में सर्वाधिक राजस्व देने के बावजूद नीमच के उप पंजीयक कार्यालय में दस्तावेजों का पंजीयन और रजिस्ट्री कराने के लिए पहुंचने वाले लोगों के लिए बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। हालात यह है कि बारिश, ठंड या गर्मी में क्रेता-विक्रेता के साथ ही गवाह भी परेशान होते हैं और शौच और पीने के पानी के लिए तक भटकना पड़ता है। दुःखद है कि जिले के सभी बड़े अधिकारी कलेक्टर कार्यालय में ही बैठते हैं तो अगर कलेक्टर में इतनी अव्यवस्थाओं का आलम है तो पुरे जिले के क्या हाल होंगे। यह मुद्दा उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस सचिव व जिला पंचायत सदस्य तरुण बाहेती ने कहा कि पंजीयन विभाग जिले का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है जो दस्तावेजों का पंजीयन करने के साथ ही संपत्तियों की रजिस्ट्री भी करता है, जिससे मिलने वाला स्टाम्प शुल्क से शासन को हर साल करोड़ों रुपए का राजस्व मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि सबसे अधिक राजस्व देने वाले विभाग की सुविधाएं भी सबसे खराब है। कांग्रेस नेता श्री बाहेती ने बताया कि नीमच कलेक्टोरेट कार्यालय में संचालित उप पंजीयन कार्यालय में जहाँ प्रतिदिन दस्तावेजों का पंजीयन व रजिस्ट्री कराने के लिए बड़ी संख्या में क्रेता-विक्रेता, गवाह, सर्विस प्रोवाइडर व क्रेता-विक्रेता के परिजन आदि पहुंचते हैं, पर ठंड हो या बारिश उन्हें कलेक्टोरेट के पीछे एक गालियारे जैसी जगह में उप पंजीयन कार्यालय की खिड़की के बाहर घंटो खड़ा रहना पड़ता है। स्थिति यह है कि जहां रजिस्ट्री कराने के लिए लोगों को खड़ा किया जाता है, वहां बैठने की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और पेयजल एवं महिलाओं के सुविधाघर तक का अभाव है। अगर किसी को सुविधाघर की जरूरत महसूस होती है तो कलेक्टोरेट में प्रवेश करना पड़ता है, जिसमें सबसे अधिक महिलाएं परेशान होती हैं तथा बच्चों के साथ आने वाली महिलाओं को तो जमीन पर बैठना पड़ता है जबकि नियमानुसार यहाँ मातृत्व कक्ष की भी निर्माण होना चाहिए जहाँ छोटे व जन्मे बच्चों के साथ आने वाली महिलाएं बच्चों को दूध भी पिला सकें।

**3 साल में 105 करोड़ रुपए कमाए नीमच उप पंजीयक कार्यालय ने-** कांग्रेस नेता श्री बाहेती ने बताया कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों का आकड़ा देखा जाए तो सिर्फ नीमच के उप पंजीयन कार्यालय ने लगभग 105 करोड़ रुपए का राजस्व दस्तावेजों के पंजीयन और रजिस्ट्रियां कर प्राप्त किया है। नीमच पंजीयन कार्यालय के रिकार्ड अनुसार पिछले वित्तीय वर्षों में प्रतिवर्ष 18500 से अधिक दस्तावेजों की

रजिस्ट्रियां हुई हैं, सम्पत्ति रजिस्ट्री करवाने वाले क्रेता-विक्रेता, गवाह के सहित 10 लोग एक रजिस्ट्री कराने उप पंजीयन में पहुँचते हैं। अगर यह आकड़ा प्रतिदिन के हिसाब से जोड़ा जाए तो लगभग 500 लोग नीमच पंजीयन कार्यालय में प्रतिदिन आते हैं। इतने अधिक लोगों के आने के बावजूद उनके बैठने की व्यवस्था भी नहीं हो पाना प्रशासन की लापरवाही एवं गलत कार्यशीलता को दर्शाती है।

**-खुद का भवन नहीं, कलेक्टोरेट में एक हाल में चल रहा दफ्तर-** श्री बाहेती ने कहा कि नीमच जिले के बने 25 वर्ष हो गए हैं लेकिन हालात यह है कि सरकार को हर साल करोड़ों रुपए का राजस्व देने वाले नीमच उप पंजीयन विभाग के पास खुद का भवन तक नहीं है। संयुक्त कलेक्टोरेट में विभाग को दो हॉल तो आवंटित है, लेकिन उपयोग एक का ही हो रहा है, उसमें भी उप पंजीयक बैठ रहे हैं, जबकि दूसरे हॉल में निर्वाचन आयोग ने कब्जा कर निर्वाचन के सामग्री रख रखी है, जबकि निर्वाचन आयोग के पास खुद का अपना भवन है। श्री बाहेती ने कहा कि तहसील कार्यालय अलग बनने के बाद कलेक्ट्रेट परिसर का ऊपर का परिसर खाली हो चुका है। कलेक्टर कार्यालय में नीचे स्थित विभागों को ऊपर की मंजिल पर स्थापित कर यहाँ पंजीयन कार्यालय कि बड़ी जगह देकर आम जनता को सुविधा देनी चाहिए।

**आरक्षित है भूमि, पर लेप्स हो चुकी है भवन निर्माण राशि** जिला पंचायत सदस्य तरुण बाहेती ने बताया कि जिला पंजीयक का भवन पूर्व में एसपी कार्यालय में बनाया गया था, लेकिन पुलिस की गोपनीयता के मद्देनजर पुलिस विभाग ने प्रशासन के हस्तक्षेप से जिला पंजीयन विभाग का भवन हैंडओवर कर लिया था, तब तत्कालीन कलेक्टर जितेंद्र राजे ने 28 नवंबर 2020 को एक आदेश पारित कर जिला पंजीयन विभाग को कलेक्टोरेट परिसर में लोकसेवा केंद्र के पास भवन निर्माण के लिए 4000 वर्ग फीट भूमि देने का आदेश जारी किया था। जहां जिला पंजीयक कार्यालय का भी निर्माण होना था, इस भवन निर्माण के लिए चीवन लाख रु राशि स्वीकृत भी हुई थी, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधि को ढीली नीति के कारण वह राशि भी लेप्स हो चुकी है। अब जिला पंजीयक कार्यालय को कलेक्टर कार्यालय में पहली मंजिल पर एक कमरा आवंटित किया जा रहा है, जिससे अब नवीन भवन बनाने की सम्भावना भी समाप्त हो गई है। श्री बाहेती ने कहा कि नीमच के विधायक दिलीप सिंह परिहार के भी संज्ञान में यह मामला है, लेकिन जनता कि परेशानी से उन्हें मतलब नहीं, अगर वें मूलभूत सुविधा भी नहीं दे पा रहें तो आखिर किस मुँह से विकास का ढिंढोरा पीटा जाता है। आज जिले का सबसे अधिक कमाई देने वाला और महत्वपूर्ण विभाग ही बंदहाल है







# पाकिस्तानी एयरलाइंस के इस विज्ञापन ने सोशल मीडिया पर मचाई हलचल

**इंटरनेशनल डेस्क.** पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की स्थिति पिछले कुछ वर्षों में काफी खराब हो चुकी है, जिसके कारण वह कर्ज में डूबी हुई है। 2020 में, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए PIA की उड़ानें प्रतिबंधित कर दी गई थीं। हालांकि, चार साल के बाद अब यह एयरलाइंस फिर से यूरोप के लिए उड़ानें शुरू करने में सफल रही है। 10 जनवरी 2024 को PIA ने घोषणा की कि उसने पेरिस के लिए अपनी उड़ानें

फिर से शुरू कर दी हैं, और अब पाकिस्तान से सीधा पेरिस के लिए उड़ान भरी जा सकेगी।पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के इस विज्ञापन ने न केवल सोशल मीडिया पर हलचल मचाई, बल्कि लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या यह एयरलाइंस अपनी छवि सुधारने के लिए सही रास्ते पर चल रही है। इस संदेश को PIA ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एक्स पर पोस्ट किया, जहां उन्होंने इस खबर को लोगों तक पहुंचाया। लेकिन एयरलाइंस

की ओर से शेयर किए गए इस पोस्ट में एक ग्राफिक शामिल था, जिसे देखकर सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने तुरंत प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। **क्या था ग्राफिक में ख़ास?** ग्राफिक में PIA ने पेरिस के लिए उड़ान की शुरुआत की जानकारी दी थी, लेकिन इसकी डिज़ाइन कुछ ऐसी थी कि कई लोगों को यह डरावना और विवादास्पद लगा। इससे पहले, PIA ने एक ग्राफिक में WTO को लेकर भी एक विवादित संदेश पोस्ट किया

था, जिसके बाद इसे 9/11 हमले से जोड़ा गया था। अब, इस नए विज्ञापन में ग्राफिक में दिखाए गए विमान के आस-पास एफ़िल टावर जैसे महत्वपूर्ण प्रतीकों को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने मजाक और आलोचना की। यह विज्ञापन वायरल होते ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। लोग हंसी-ठिठोली करते हुए लिखने लगे कि क्या PIA इस विज्ञापन के जरिए किसी को डराने की कोशिश कर रही है? एक यूजर ने तो यह तक लिखा कि क्या यह

जानकारी दे रहे हैं या पेरिस में होने वाली किसी आपात स्थिति के लिए चेतावनी दे रहे हैं? वहीं कुछ यूजर्स ने तो मजाक करते हुए कहा, अरे भाई, एफ़िल टावर को गिरा मत देना ! इसके साथ ही कुछ यूजर्स ने यह भी सवाल उठाया कि पेरिस सरकार ने इस एयरलाइन को उड़ान की मंजूरी कैसे दी, जबकि यह एयरलाइंस पहले ही अपनी खराब छवि और प्रतिबंधों के कारण आलोचनाओं का सामना कर चुकी है। एक यूजर

ने कहा, पेरिस ने इस एयरलाइन को कैसे मंजूरी दी? क्या उन्होंने इसके पिछले इतिहास को देखा था? **PIA की स्थिति** PIA पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइंस है, लेकिन इसके लिए यह चुनौतीपूर्ण समय है। आर्थिक संकट, कर्ज और खराब वित्तीय स्थिति के कारण PIA को कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए बैन का सामना करना पड़ा था। हालांकि, चार साल के बाद अब उसने यूरोप के

लिए उड़ानें फिर से शुरू की हैं, जिससे उसे उम्मीद है कि वह अपने गिरते हुए राजस्व को सुधार सकेगा। हालांकि, सोशल मीडिया पर किए गए इस विवादास्पद विज्ञापन के बाद PIA को यह समझने की जरूरत है कि इस तरह के विज्ञापन और ग्राफिक्स को संवेदनशीलता और ध्यानपूर्वक डिज़ाइन करना चाहिए, ताकि यह किसी को भी नुकसान न पहुंचाए और कंपनी को छवि को भी नुकसान न हो।

# सत्ता से छोड़ने से पहले छलका बाइडेन का दर्द- मैं ट्रंप को चुनाव में हरा देता लेकिन...

**इंटरनेशनल डेस्क.** अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वह नवंबर में हुए आम चुनावों में ट्रंप को हरा देते लेकिन उन्होंने डेमोक्रिटिक पार्टी की एकजुटता की खातिर चुनाव के बीच उम्मीदवारी वापस लेने का फैसला किया। बाइडन से शुक्रवार को यहां व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में पूछा गया, राष्ट्रपति महोदय, क्या आपको चुनाव न लड़ने के अपने फैसले पर खेद है? क्या आपको लगता है कि आपने अपने पूर्ववर्ती (ट्रंप) को अपना उत्तराधिकारी बनने का आसान मौका दिया? इसपर बाइडेन ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं ट्रंप को हरा देता, हरा सकता था। मुझे लगता है कि कमला (हैरिस) ट्रंप को हरा सकती थीं।

**पार्टी को एकजुट करने के लिए लिया फैसला**

उन्होंने कहा, पार्टी को एकजुट करना महत्वपूर्ण है और जब पार्टी इस बात को लेकर चिंतित थी कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं, तो मैंने सोचा कि पार्टी को एकजुट करना बेहतर होगा। हालांकि मुझे लगा था कि मैं फिर से जीत सकता हूं। जून में अटलांटा में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच हुई 'डिबेट में बाइडेन (82) का प्रदर्शन कुछ खास नहीं था जिसके बाद से उनकी ही पार्टी के सदस्य बाइडेन के इस पद की दौड़ से हटने की बात करने लगे थे और अंततः बाइडेन ने ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटने का फैसला किया था। बाइडेन की जगह उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया था। हालांकि उन्हें ट्रंप के हाथों हार का सामना करना पड़ा।

**कमला हैरिस फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने में सक्षम**

संवाददाता सम्मेलन के दौरान बाइडेन ने कहा



कि कमला हैरिस फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह एक ऐसा निर्णय है जिसके बारे में वह सोच सकती हैं। वह चार साल बाद फिर से चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। यह निर्णय उन्हें ही लेना होगा। इस दौरान बाइडेन से पूछा गया, क्या आप राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी सक्रिय रहने की योजना बना रहे हैं, या आप बुश मॉडल का अनुसरण करने जा रहे हैं, जहां आप लोगों की नजरों से ओझल रहेंगे? इसका जवाब देते हुए बाइडेन ने कहा, मैं न तो नजरों से ओझल होऊंगा और न ही दिलों से। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता बाइडेन 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद छोड़ देंगे। उनकी जगह डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। रिपब्लिकन पार्टी के ट्रंप बाइडेन से पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं।

**बुधवार को अंतिम भाषण देंगे बाइडेन**

बाइडेन नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से पांच दिन पहले बुधवार को ओवल ऑफिस से विदाई भाषण देंगे। बीस जनवरी को पद छोड़ने से पहले यह राष्ट्रपति के तौर पर अमेरिकियों और दुनियाभर के लोगों के लिए बाइडेन का अंतिम भाषण होगा, जो रात आठ बजे आरंभ होगा। वह सोमवार को विदेश मंत्रालय में अपने कार्यकाल की विदेश नीति पर केंद्रित एक भाषण देंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव केरिन जीन-पियरे ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि बाइडेन सोमवार को अपने भाषण में “‘50 से अधिक वर्षों के अपने सार्वजनिक जीवन पर बात करेंगे। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच हुई 'डिबेट में बाइडेन (82) का प्रदर्शन कुछ खास नहीं था।

# लड़कों के साथ फोन पर बात करने से रोकती थी मां, नाराज बेटी ने कुल्हाड़ी से कर दी हत्या

**नेशनल डेस्क.** बिहार में एक कलयुगी बेटी ने अपनी विधवा मां की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। दरअसल, मां उसे लड़कों के साथ फोन पर बात करने से रोकती थी, जो बात लड़की को पसंद नहीं आई। इससे नाराज होकर लड़की ने खोफनाक कदम उठाया और अपनी मां की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटी को गिरफ्तार कर लिया है।

**कई लड़कों से फोन पर बात करती थी बेटी**

दरअसल, यह दिल दहला देने वाली घटना पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के घिउवाढार गांव की है। बताया जा रहा है कि मंजू देवी अपनी बेटी सोनी के साथ घर में रहती थी। सोनी कई लड़कों से फोन पर बात करती थी। उसकी इस



आदत को लेकर मां अक्सर उसे डांटती थी। वहीं 5 जनवरी को भी इसी बात लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। इसी दौरान सोनी ने गुस्से में आकर अपनी मां मंजू देवी की कुल्हाड़ी से

हत्या कर दी। **वारदात के बाद हुई फरार** इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद उसने खुद लगे कपड़े धोए और घर को बाहर से बंद कर फरार हो गई। इस मामले में

डीएसपी रंजन कुमार ने बताया कि पुलिस को 5 जनवरी को एक बंद कमरे में महिला की खून से सनी लाश मिली थी। शव के पास ही कुल्हाड़ी रखी हुई थी। वहीं स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद पता चला कि मृतका अपनी बेटी के साथ रहती थी, जो घटना के बाद से फरार थी।

**बेटी ने कबूल किया अपना जुर्म**

शक के आधार पर पुलिस ने डॉग स्कायड और एफएसएल की टीम के साथ जांच शुरू की। एसपी ने डीएसपी रंजन कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया। वहीं 4 दिन की छानबीन के बाद पुलिस ने आरोपी बेटी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है।



**इंटरनेशनल डेस्क.** अमेरिका के लॉस एंजिल्स काउंटी में पिछले कुछ दिनों से आग ने भारी तबाही मचाई है। लॉस एंजिल्स काउंटी के एक हिस्से में 3 अरब रुपये का आलीशान घर भी पूरी तरह से जल गया।इस आग ने 10,000 से जादा घरों को जलाकर खाक कर दिया है और पैसिफिक पैलिसेड्स और मालिबू जैसे इलाकों के 19,000 एकड़ से जादा क्षेत्र को बर्बाद कर दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह

है कि इतनी भयानक आग के बावजूद लॉस एंजिल्स की हवा दिल्ली की तुलना में काफी साफ है। 10 जनवरी को लॉस एंजिल्स का एयर क्वालिटी इंडेक्स 154 दर्ज किया गया, जो कि दिल्ली के AQI से काफी बेहतर है। इस समय दिल्ली का AQI 372 है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। इससे यह साफ होता है कि सामान्य दिनों में भी अमेरिकी शहरों में एयर क्वालिटी काफी अच्छी रहती है।

दिल्ली की हवा खराब, जबकि रू.में आग के बावजूद साफ सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लॉस एंजिल्स और दिल्ली के ८त्क्ष की तुलना करते हुए लिखा कि, आधा LA जल रहा है, फिर भी वहां की हवा दिल्ली से साफ है। वहीं, कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि दिल्ली की खराब हवा में हरियाणा और पंजाब के किसानों द्वारा पराली जलाने का भी असर है, जिससे धुंआ दिल्ली तक पहुंचता है।

# दिल्ली चुनाव में मुफ्त योजनाओं पर भाजपा, कांग्रेस और आप की नजरें

**नेशनल डेस्क.** दिल्ली विधानसभा चुनाव अब मुफ्त योजनाओं के मुद्दे पर गहराई से प्रभावित हो गया है। आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा शुरू की गई मुफ्त योजनाओं को पहले मुफ्त की रेवड़ी और मुफ्तखोरी के रूप में आलोचना का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब यह तरीका भाजपा और कांग्रेस जैसी अन्य पार्टियों द्वारा भी अपनाया जा रहा है। कुल मिलाकर दिल्ली के चुनावी दंगल में तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों की उम्मीदें मुफ्त योजनाओं पर ही टिकी हुई हैं। दिल्ली में मुफ्त बिजली और पानी देने के वादे ने आम आदमी पार्टी को सत्ता में बैठाया था, लेकिन अब इन मुफ्त योजनाओं का राज्य पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। दिल्ली सरकार का बजट लगभग 76,000 करोड़ रुपये का है, जिसमें से

15-20ब हिस्सा मुफ्त योजनाओं के लिए आवंटित किया जाता है। दिल्ली सरकार हर साल 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए लगभग 3,250 करोड़ रुपये खर्च करती है। इसके अलावा, मुफ्त पानी और अन्य सस्मिडी के कारण राज्य के खजाने पर भारी दबाव पड़ रहा है। यदि अरविंद केजरीवाल द्वारा महिला सम्मान योजना लागू की जाती है, तो इससे दिल्ली सरकार पर 4,560 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च हो सकता है। इसके अलावा, भाजपा और कांग्रेस ने भी चुनावी वादों के तहत कई मुफ्त योजनाओं की घोषणा की है। भाजपा ने वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए भी बिजली सस्मिडी देने का वादा किया है, जबकि कांग्रेस ने 400 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना बनाई है। कांग्रेस ने इसके अतिरिक्त, प्रत्येक निवासी के

लिए 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और महिलाओं को 2,500 रुपये मासिक सहायता देने का वादा किया है। इन घोषणाओं के चलते दिल्ली सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि मुफ्त योजनाओं पर भारी खर्च किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के वित्तीय विशेषज्ञों का मानना ​​है कि राज्य को अगले कुछ वर्षों में भारी घाटे का सामना करना पड़ सकता है। अगर इन योजनाओं को पूरे राज्य में लागू किया गया, तो सरकार को इसके लिए और अधिक संसाधन जुटाने की आवश्यकता पड़ेगी। दिल्ली के अलावा, अन्य राज्यों में भी मुफ्त योजनाओं के बोझ का सामना किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर, महाराष्ट्र में भाजपा सरकार द्वारा लाड़की बहिन योजना को लेकर वित्तीय संकट का सामना किया जा रहा है। चुनाव से

पहले इस योजना के तहत राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया था। बाद में, इस राशि को बढ़ाकर 2,100 रुपये करने का भी वादा किया गया। इसके लिए सरकार को हर साल लगभग 63,000 करोड़ रुपये चाहिए। पिछले साल के बजट में महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना के लिए 46,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, लेकिन अब राज्य सरकार को इस भारी बोझ को उठाने में कठिनाई हो रही है। राज्य के कृषि मंत्री ने हाल ही में कहा कि लाड़की बहिन योजना के कारण कृषि ऋण माफी योजना को लागू करने में दिक्कत आ रही है। हिमाचल प्रदेश में भी सुकसू सरकार ने मुफ्त योजनाओं का वादा किया था। राज्य सरकार ने महिलाओं को 1,500 रुपये और 125

यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। जब इन योजनाओं को लागू किया गया, तो राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई। यहां तक ​​कि 1 सितंबर 2024 को राज्य के 2.5 लाख सरकारी कर्मचारियों और 1.5 लाख पेंशनर्स के खातों में न तो सैलरी आई, न ही पेंशन। सरकार ने जरूरी योजनाओं पर खर्च करने में कठिनाई महसूस की और बाद में बिजली सस्मिडी छोड़ने की अपील की। अनुमान है कि 2024-25 में हिमाचल का वित्तीय घाटा 10,784 करोड़ रुपये तक जा सकता है। झारखंड में भी हेमंत सोरेन सरकार ने मुफ्त योजनाओं के जरिए सत्ता हासिल की थी। यहां मड़या सम्मान योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह दिए जा रहे थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया। इसके

अलावा, राज्य सरकार ने मुफ्त बिजली देने की योजना भी लागू की है। लेकिन इन योजनाओं का बोझ राज्य के खजाने पर बढ़ रहा है। जनवरी 2025 में इस योजना के तहत महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर करते समय राज्य खजाने पर एक महीने के लिए 1,415 करोड़ रुपये का बोझ पड़ा। यदि यह योजना जारी रहती है, तो राज्य सरकार को सालाना 16,980 करोड़ रुपये का खर्च उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने केंद्र से 1.36 लाख करोड़ रुपये का फंड मांगा है, जो राज्य को मिलनी वाली कोयला रॉयल्टी का हिस्सा है। इसका साफ मतलब है कि मुफ्त योजनाओं का बोझ सरकारों के लिए भारी पड़ सकता है। हालांकि, अगर इन योजनाओं को रणनीतिक रूप से लागू किया जाए तो ये नकारात्मक नहीं हो